राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 25 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-234 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

लद्दाख के लिए वांगचुक की पदयात्रा, सीजेपी के बड़े नेता नदारद

उपराज्यपाल ने वापस लिए 20 केस

नई दिल्ली।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में 26 दिनों तक अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बदले में वह व्यापक साथ नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने आवाज लगाई थी। सोनम वांगचुक की लद्दाख पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए सीजेपी का एक भी बड़ा नेता लद्दाख नहीं गया। अभिजीत दीपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समर्थन की बात तो कही थी, लेकिन खुद वहां जाने से परहेज कर गए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर 2025 को केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। इसकी पहली बरसी के उपलक्ष्य में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को लेह में एक प्रतीकात्मक पदयात्रा का नेतृत्व किया। 24 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले सोनम वांगचुक ने 19 से 24 सितंबर तक पदयात्रा की घोषणा करते हुए कॉकरोचों (सीजेपी सदस्यों) से भी इसमें शामिल होने की अपील की थी। दिल्ली से बनाए एक वीडियो में वांगचुक ने जंतर-मंतर पर अपने अनशन की याद दिलाते हुए कहा था कि वह अब कॉकरोचों से मदद चाहते हैं। वांगचुक की अपील पर अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने लद्दाख के समर्थन की बात सोशल मीडिया पर लिखी थी। हालांकि, इनमें से किसी नेता ने ना तो लद्दाख जाने की घोषणा की थी और ना ही इनकार किया था। बाद में वांगचुक ने खराब मौसम को देखते हुए चार दिन की यात्रा स्थगित कर दी और सिर्फ 23 सितंबर को एक दिन की पदयात्रा की घोषणा की। बुधवार को जब कुछ दर्जन यात्रियों के साथ वांगचुक लेह की ओर रवाना हुए तो उनके साथ लद्दाख के अलावा कुछ दूसरे प्रदेशों से आए लोग भी थे। हालांकि, सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका वहां नजर नहीं आए। पदयात्रा के दौरान एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वांगचुक ने कहा कि उन्होंने एक बार अधिक से अधिक लोगों के आने की अपील की थी, लेकिन बाद में इस पर अधिक जोर नहीं दिया, जो आए उनका स्वागत किया गया है।

जमुई के बाद समस्तीपुर में युवती से सरेराह अभद्रता, पांच हिरासत में

बांध बाइपास रोड पर फोटो लेने के दौरान युवकों ने घेरा, पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और आरोपों की कर रही जांच

समस्तीपुर ।

बिहार के जमुई में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला अभी चर्चा में था कि समस्तीपुर से भी एक युवती के साथ कथित अभद्रता का वीडियो सामने आया है। कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव स्थित बांध बाइपास रोड पर युवती को कुछ युवकों द्वारा घेरने और उसके साथ गाली-गलौज व बदसलूकी करने का आरोप है। घटना का वीडियो बुधवार देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

स्थानीय लोगों के अनुसार, युवती एक युवक के साथ सड़क किनारे रुककर फोटो ले रही थी। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और युवती को घेर लिया। वायरल वीडियो में कुछ युवक उससे नाम-पता पूछते और कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवती के साथ कथित तौर पर गलत तरीके से छूने और सड़क पर खींचने जैसी हरकतों के आरोप भी सामने आए हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान शुरू की।

पुलिस के मुताबिक अब तक विकास शर्मा और राहुल कुमार की पहचान हुई है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार विकास शर्मा के खिलाफ शराब से जुड़े मामले पहले दर्ज हैं। पुलिस वीडियो के स्रोत, घटना के समय और पूरे घटनाक्रम की पुष्टि कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की भूमिका और घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट.....महाभियोग लाने की तैयारी

नई दिल्ली ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें चुनाव आयोग और एसआईआर से जुड़े खुलासों के बाद बढ़ती जा रही हैं। अब विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष संसद के दोनों सदनों में जल्द ही महाभियोग संबंधी नोटिस देगा। सूत्रों के मुताबिक, इसका मसौदा तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों में मसौदा पेश किया जा सकता है। खास बात यह है कि महाभियोग का नोटिस देने के लिए संसद सत्र का चालू रहना आवश्यक नहीं है, जिससे यह प्रक्रिया किसी भी समय शुरू की जा सकती है।

एमएमडीआर संशोधन एक्ट को लेकर ओडिशा विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा

भुवनेश्वर।

ओडिशा विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन कामकाज में बाधा आई। विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) और कांग्रेस के विधायकों ने एमएमडीआर संशोधन एक्ट को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेडी और कांग्रेस के सदस्य पिछले दो दिनों से अलग-अलग मुद्दों पर सदन में विरोध कर रहे थे। हालांकि, बीजेडी के विधायक पिछले दो दिनों से स्कूली किताबों में छपाई की गलतियों को लेकर स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने गुरुवार को एमएमडीआर संशोधन एक्ट को लेकर सदन में हंगामा किया और इसे रद्द करने की मांग की। मानसून सत्र के तीसरे दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो कांग्रेस और बीजेडी के विधायकों ने स्पीकर के आसन के पास पोस्टर और बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और एमएमडीआर संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की। इस हंगामे के बीच, डिप्टी स्पीकर भबानी शंकर भोई ने कार्यवाही चलाने की कोशिश की और प्रश्न काल के दौरान मंत्री मुकेश महालिंग और सुरेश पुजारी ने सवालों के जवाब दिए।

इस दौरान, विपक्षी विधायकों के लगातार हंगामे के कारण डिप्टी स्पीकर को सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

युवाओं से बोले पीएम मोदी- आचरण से दें सेवा का संदेश

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत वडनगर से वाराणसी जा रहे युवाओं के दल से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए युवाओं से अपने आचरण के जरिए सेवा का संदेश देने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि सेवा पर उपदेश देने के बजाय सेवा करके उसका संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कितनी भी बड़ी सत्ता या जिम्मेदारी मिले, रास्ता हमेशा सेवा का ही होना चाहिए और 'सेवा परमो धर्म॰' की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने यात्रा की परंपरा का उल्लेख करते हुए सेवा यात्रियों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि यात्रा से लौटे व्यक्ति को प्रणाम करने वाले को यात्रा के पुण्य का आधा हिस्सा मिलता है। उन्होंने कहा कि वह भी सेवा यात्रियों को प्रणाम कर उनका आधा पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण की एक तकनीक भी साझा की। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के बाद उसके पास पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखा जा सकता है। महीने में एक बार घड़े को पानी से भरने से पौधे को पानी मिलता रहेगा। उनके मुताबिक, इससे पानी की बचत के साथ अधिक पेड़ उगाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने वडनगर और वाराणसी को हजारों वर्षों से जीवंत ऐतिहासिक शहर बताते हुए कहा कि एक उनकी जन्मभूमि और दूसरा कर्मभूमि है। वडनगर को हाटकेश्वर महादेव और वाराणसी को बाबा विश्वनाथ की आशीर्वाद की भूमि बताते हुए उन्होंने यात्रा से जुड़े युवाओं के अनुभवों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवाभाव से किए गए काम का असर समाज के जरूरतमंद वर्गों तक दिखाई देता है। उन्होंने मुफ्त अनाज, आयुष्मान योजना, पीएम-किसान और पीएम सूर्य घर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं में अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने पर जोर है। उन्होंने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और भविष्य की बड़ी लाभार्थी भी। इसके लिए युवाओं को देश को जमीन पर जानने, विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों से मिलने तथा लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाशक्ति की बड़ी भूमिका

होगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था अपनी जगह हैं, लेकिन उनका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। सेवा संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर 2026 से शुरू किया गया व्यापक जनसेवा और सुशासन अभियान है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा॰ फ्री एलपीजी पर घमासान, 12 की जगह 6 सिलेंडर का ऐलान

श्रीनगर ।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को फ्री एलपीजी सिलेंडर को लेकर ज़ोरदार हंगामा हुआ। फूड, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने योग्य परिवारों को 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की नीति को मंजूरी दे दी है।

इस घोषणा पर विपक्ष ने तुरंत कड़ी आपत्ति जताकर आरोप लगाया कि उमर सरकार अपने वादे से मुकर गई है। नेता शर्मा ने याद दिलाया कि लगभग दो साल पहले सरकार ने हर घर के लिए 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि वादे की संख्या को घटाकर 6 करना लोगों के साथ मज़ाक और बड़ा धोखा है। सदन में विपक्ष ने झूठी सरकार और यह धोखा है जैसे नारे लगाए। शर्मा ने सरकार पर लोगों के सामने बेनकाब होने और अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि उमर सरकार के एक लाख नौकरियों के पहले के वादे का क्या हुआ। तीखी बहस के बाद भी, विपक्ष ने कार्यवाही के दौरान लगातार नारेबाजी जारी रखी, जिससे सदन में गहमागहमी बनी रही।

राममंदिर के बाद अब सबरीमाला मंदिर में चोरी, असली की जगह नकली मुकुट रखा मिला

हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही जांच में मुकुट में हुआ खुलासा, असली-नकली की हुई पहचान

तिरुवंनपुरम।

सबरीमाला मंदिर में एक बार फिर सोने के आभूषण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सन्निधानम के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा 446 ग्राम का सोने का मुकुट गायब मिला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां असली मुकुट की जगह नकली मुकुट रखा मिला यानी किसी ने सिर्फ सोना गायब नहीं किया बल्कि असली गहने को हटाकर उसकी जगह दूसरा मुकुट रख दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले का खुला तब हुआ जब मंदिर के पवित्र आभूषणों की गिनती और जांच चल रही थी। यह जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर जस्टिस के टी शंकरन की अगुवाई में हो रही है। जांच में मुकुट को लेकर यह बड़ा अंतर सामने आया। अब सुरक्षा व्यवस्था से लेकर उस दौरान जिम्मेदार रहे अधिकारियों और कर्मचारियों तक पर सवाल उठ रहे हैं। यह मुकुट साल 2012 में तमिलनाडु के भक्तों ने सबरीमाला मंदिर में अर्पित किया था। इसे सन्निधानम से आरणमुला के मुख्य स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाना था, लेकिन मुकुट को ऐसी जगह रखा गया जहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी नहीं थी। अब जांच में सामने आया है कि स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद मुकुट नकली है। इसी जांच में आरणमुला देवस्वोम के स्ट्रॉन्ग रूम से चार ग्राम की सोने की

माला भी गायब मिली। एक तरफ सोने का मुकुट गायब है और दूसरी तरफ सोने की माला भी नहीं मिल रही। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ना तय माना जा रहा है। देवस्वोम बोर्ड ने भी सुरक्षा चूक समेत सभी पहलुओं की जांच की बात कही है। सन्निधानम के स्ट्रॉन्ग रूम में 446 ग्राम का सोने का मुकुट रखा था। जांच के दौरान पता चला कि असली मुकुट वहां नहीं है। उसकी जगह नकली मुकुट रखा था। जांच टीम ने गिनती और सत्यापन के दौरान इस अंतर को पकड़ा।हाईकोर्ट के निर्देश पर मंदिर के तिरुवाभरणों की गिनती और जांच चल रही है। इसी दौरान असली मुकुट की जगह नकली मुकुट रखे होने की जानकारी सामने आई।

आंध्र-ओडिशा तट से टकराया अर्नब चक्रवात, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

ओडिशा में 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त; बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट

भुवनेश्वर ।

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अर्नब देर रात करीब 11 बजे से 1 बजे के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराया। इसके प्रभाव से दोनों राज्यों के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ओडिशा में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर करीब 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। दक्षिणी जिलों में भारी बारिश के कारण चार से अधिक पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कलिंगपट्टनम और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। विजयवाड़ा में भी सुबह से लगातार बारिश जारी है। इसके कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। शहर के कई स्कूलों में लगातार दूसरे दिन छुट्टी घोषित की गई है।मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती सिस्टम पिछले छह घंटे में करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। इसके प्रभाव से आने वाले समय में कुछ क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है।

चक्रवात का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है।

रायबरेली में अखिलेश यादव को कृष्ण और सपा नेता को सुदामा दिखाने वाला पोस्टर

पीडीए रथ के पहुंचने से पहले लगाया गया पोस्टर चर्चा में, सपा विधायक राहुल लोधी ने किया बचाव

लखनऊ ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को 'पीडीए रथ' के जरिए रायबरेली पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले शहर के मुख्य मार्ग पर लगाया गया एक पोस्टर चर्चा में आ गया। सपा युवजन सभा के प्रदेश सचिव एडवोकेट विश्वास दुबे की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव के सिर पर मोरपंख वाला मुकुट, पीले वस्त्र और हाथ में बांसुरी दिखाई गई है। वहीं विश्वास दुबे को सुदामा के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर पर अखिलेश यादव को 'पीडीए महानायक' बताया गया है और लिखा है, 'मेरे माधव, आपका सुदामा की धरती रायबरेली में स्वागत है।' पोस्टर सामने आने के बाद हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधी ने

प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्टर का बचाव करते हुए कहा कि द्वापर युग में सुदामा भगवान कृष्ण के साथी थे और यह परंपरा उसी समय से चली आ रही है। उनके मुताबिक, इसलिए उन्हें इस तरह के पोस्टर से कोई आपत्ति नहीं है। लोधी ने इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता समाज को जाति के आधार पर बांटने और लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं।

निजी तेल कंपनियों ने डीजल बिक्री पर लगाई सीमा॰ बढ़ती लागत का दबाव

मुंबई ।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ईंधन संकट के बीच, कुछ निजी तेल कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमित की है। रिपोर्ट के अनुसार, जियो-बीपी के कुछ पंपों पर अब एक ग्राहक को अधिकतम 50 लीटर डीजल दिया जा रहा है, जबकि कुछ आउटलेट्स पर कुल दैनिक बिक्री 6,000 लीटर तक सीमित की गई है। इसी तरह, नायरा एनर्जी के कुछ पंपों पर एक बार में 70 से 200 लीटर तक डीजल देने की सीमा है। हालांकि, यह पाबंदी फिलहाल पूरे देश में लागू नहीं है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने स्पष्ट किया है कि वे अपने 90 प्रतिशत से अधिक फ्यूल स्टेशनों पर बिना किसी सीमा के ईंधन बेचना जारी रखे हुए हैं।

इसका मतलब है कि यह असर अभी सीमित है।इस सीमित पाबंदी का सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी के ट्रकों और अन्य कारोबारी वाहनों पर पड़ सकता है, जिन्हें अब रास्ते में कई जगह रुककर ईंधन भरवाना पड़ सकता है। इन नई पाबंदियों की मुख्य वजह तेल कंपनियों को कच्चे तेल की लागत में भारी बढ़ोतरी से हो रहा नुकसान है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अंत्योदय : विकसित भारत की मानवीय आधारशिला

(लेखक – ललित गर्ग)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती (अंत्योदय दिवस),

25 सितंबर 2026 पर विशेष)

भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ यह जिम्मेदारी भी बढ़ती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही और 2026-27 की पहली तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत रही। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी सार्वजनिक नीति और आर्थिक विमर्श में प्रमुखता से व्यक्त किया गया है, 2026 के केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया में भी यह लक्ष्य दोहराया गया।

भारत की विकास यात्रा आज ऐसे दौर में है, जब आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रभाव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। 2026–27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है और देश को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन किसी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद, ऊंची इमारतों, आधुनिक सड़कों या वैश्विक रैंकिंग से तय नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी कसौटी यह है कि विकास की रोशनी उस व्यक्ति तक कितनी पहुंची है, जो विकास की कतार में सबसे पीछे खड़ा है। यहीं से अंत्योदय का विचार प्रासंगिक होता है। हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का दिन है और 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने इसे अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को भी शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ना था। इसलिए अंत्योदय दिवस केवल किसी महापुरुष की स्मृति का दिवस नहीं, बल्कि विकास की दिशा और उसकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का अवसर है।

'अंत्योदय' दो शब्दों से बना है–'अंत्य' अर्थात सबसे अंतिम और 'उदय' अर्थात उत्थान। लेकिन इसका अर्थ केवल किसी गरीब व्यक्ति को सहायता देना नहीं है। अंत्योदय का व्यापक अर्थ है–ऐसी व्यवस्था का निर्माण जिसमें कोई व्यक्ति अवसरों से वंचित न रहे, कोई परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पीछे न छूटे और विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' में मनुष्य केवल आर्थिक उत्पादन की इकाई नहीं है। उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा–सभी का संतुलित विकास आवश्यक है। यही अंत्योदय को महज कल्याणकारी कार्यक्रम से आगे ले जाकर मानव–केंद्रित विकास–दर्शन बनाता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि भारत विकास कर रहा है या नहीं। प्रश्न यह है कि भारत के विकास का लाभ किस गति से, किस गहराई से और किस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यही वह प्रश्न है जो अंत्योदय दिवस को 2026 में और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।

भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक आकार बढ़ाने का लक्ष्य नहीं हो सकता। विकसित भारत का अर्थ विकसित गांव, सक्षम नागरिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पहुंच, उद्यमिता और अवसरों की समान उपलब्धता भी है। 2026 में नीति–निर्माण में 'समावेशी मानव विकास' को विकसित भारत की चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। यही कारण है कि आज अंत्योदय की आवश्यकता पहले से कम नहीं, बल्कि अधिक है। आर्थिक विकास जितना तेज होगा, उतनी ही जरूरी होगी यह सावधानी कि विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूट जाए। तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी, उतना ही जरूरी होगा कि डिजिटल विभाजन कम हो। नए रोजगार जितने पैदा होंगे, उतनी ही आवश्यकता होगी कि गरीब और ग्रामीण युवा उनके लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े करोड़ों श्रमिकों के संदर्भ में नीति आयोग ने भी यह रेखांकित किया है कि तकनीक अपने आप समावेशी परिवर्तन नहीं ला सकती, अवसरों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

इस दृष्टि से अंत्योदय का नया अर्थ 'सहायता से सशक्तिकरण' होना चाहिए। गरीब को केवल अनुदान नहीं, अवसर मिले। किसान को केवल राहत नहीं, बेहतर उत्पादकता और बाजार मिले। श्रमिक को केवल रोजगार नहीं, कौशल और सामाजिक सुरक्षा मिले। महिला को केवल कल्याणकारी योजना नहीं, शिक्षा, संपत्ति, उद्यमिता और निर्णय–क्षमता में भागीदारी मिले। ग्रामीण युवा को केवल नौकरी की तलाश में शहर की ओर जाने की मजबूरी न हो, बल्कि उसके गांव और कस्बे में ही कौशल, डिजिटल सुविधा और उद्यम का वातावरण बने। यही अंत्योदय का आधुनिक स्वरूप हो सकता है–व्यक्ति को लाभार्थी से भागीदार बनाना। 2014 में शुरू हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना ने ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आजीविका तथा कौशल–विकास को महत्व दिया था। सरकार ने उस समय ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के उत्थान के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को विस्तार देने की बात कही थी। आज आवश्यकता इस सोच को और व्यापक बनाने की है। अंत्योदय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल, आवास, पोषण, वित्तीय समावेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामाजिक सुरक्षा के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण बनाना होगा।

भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ यह जिम्मेदारी भी बढ़ती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025–26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही और 2026–27 की पहली तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत रही। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी सार्वजनिक नीति और आर्थिक विमर्श में प्रमुखता से व्यक्त किया गया है, 2026 के केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया में भी यह लक्ष्य दोहराया गया। लेकिन आर्थिक महाशक्ति बनने की यात्रा तभी व्यापक अर्थों में सफल होगी, जब आर्थिक शक्ति का सामाजिक आधार भी उतना ही मजबूत हो। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा केवल विश्व को ज्ञान देने से पूरी नहीं होगी, अपने समाज के अंतिम व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने से भी उसकी परीक्षा होगी। भारत की प्राचीन चेतना में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे विचार रहे हैं। अंत्योदय इसी मानवीय परंपरा का आधुनिक सामाजिक–आर्थिक रूप माना जा सकता है। यह कहता है कि राष्ट्र की समृद्धि का अर्थ केवल कुछ लोगों की समृद्धि नहीं, बल्कि समूचे समाज की उन्नति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को जीवंत रखने का सबसे सार्थक तरीका केवल उनके चित्र पर माल्यार्पण करना नहीं, बल्कि उनके विचार के मानवीय पक्ष को व्यवहार में उतारना है। उनका जीवन सादगी, संगठन, राष्ट्रसेवा और वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ा रहा। उनका अंत्योदय दर्शन आने वाली पीढ़ियों को यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है कि हमारे विकास का अंतिम लाभार्थी कौन है और क्या वह वास्तव में विकास की मुख्यधारा में आ पाया है?

2047 का विकसित भारत केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बनेगा। इसके लिए शासन, समाज, उद्योग, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और नागरिकों–सभी की भागीदारी आवश्यक होगी। गांवों में स्थानीय उद्यमिता बढ़ानी होगी, युवाओं को कौशल देना होगा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नई तकनीकें इस पहुंच को तेज कर सकती हैं, 2026 में नीति आयोग की डीपीआई–2047 रूपरेखा ने भी डिजिटल अवसंरचना को समावेशी और उत्पादकता–आधारित विकास से जोड़ा है। अंत्योदय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राष्ट्र की प्रगति को ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर भी देखना होगा। जब अंतिम गांव आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। जब अंतिम परिवार आत्मनिर्भर होगा, भारत मजबूत होगा। जब अंतिम बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाएगा, भारत का भविष्य मजबूत होगा। जब अंतिम श्रमिक को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, भारत की विकास यात्रा अधिक मानवीय होगी।

अंत्योदय दिवस इसलिए केवल 25 सितंबर का एक स्मृति–दिवस नहीं होना चाहिए। इसे राष्ट्र के विकास की नैतिक कसौटी बनाने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को युगों तक जीवित रखने वाला सबसे प्रभावी स्मारक कोई भवन या प्रतिमा नहीं, बल्कि ऐसा भारत होगा जिसमें अंतिम व्यक्ति स्वयं को व्यवस्था से बाहर नहीं, बल्कि राष्ट्र की मुख्यधारा का सम्मानित भागीदार महसूस करे। विकसित भारत की ऊंचाई उसकी आर्थिक शक्ति से दिखाई देगी, लेकिन उसकी वास्तविक महानता इस बात से पहचानी जाएगी कि उसकी विकास–यात्रा कितनी दूर तक और कितने लोगों तक पहुंची है। अंत्योदय उसी यात्रा का मानवीय आधार है। 2047 का भारत यदि समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण बनना चाहता है, तो विकास की हर मंजिल पर उसे एक बार पीछे मुड़कर उस अंतिम व्यक्ति को देखना होगा–क्योंकि जिस दिन अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, उसी दिन भारत के उदय की पूर्णता होगी।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

जवाबदेही तय हो

विकसित व पश्चिमी देशों में गंभीर रोगों और सर्जरी तक में कम से कम दवा देने की नीति का सख्ती से पालन किया जाता है। इसके उलट हमारे देश में खांसी–जुकाम व सामान्य बुखार में भी पेनकिलर्स और एंटीबायोटिक्स का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। हम मेडिकल स्टोरों से दवा खरीद लाते हैं और खुद ही चिकित्सक बन जाते हैं। यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण तमाम रोगियों पर ये दवाइयां कालांतर असर नहीं करती हैं। जो एक गंभीर चिकित्सीय खतरों की ओर इशारा करती है। ऐसे में दर्द कम करने वाली दवाओं यानी पेनकिलर्स और एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन की हालिया सलाह, पब्लिक हेल्थ संकट की गंभीरता को ही दर्शाती है। यह विडंबना ही है कि जिन दवाओं का इस्तेमाल बेहद जरूरी होने तथा डॉक्टर की सलाह पर होना चाहिए, उन्हें हम अक्सर बचाव के तौर पर या मामूली संक्रमण के लिये भी लेने लगते हैं। दरअसल, हमारे शरीर का जैविक सुरक्षातंत्र खासा मजबूत होता है, जो मामूली संक्रमण व बीमारियों से खुद ही निबट सकता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया कुदरती तौर पर धीमी होती है। यह बेहद चिंता की बात है कि एंटीबायोटिक्स के जरूरत से ज्यादा और गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति ने देश को ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस संकट के केंद्र में ला खड़ा किया है। इस संकट की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन दवाओं के दुरुपयोग को लेकर आम लोगों की जानकारी बेहद कम है। जिसका लाभ आधी–अधूरी डिग्रियों वाले नीम–हकीम उठाते हैं और जल्दी ठीक करने का दावा करके मरीजों से कमाई करते हैं। लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते कि इन दवाओं के बुरे असर यानी दवा के विपरीत रिएक्शन से किडनी आदि की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अधिक दवाइयां लेने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दरअसल, बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाइयों की सहज उपलब्धता तथा लोगों में बढ़ती सेल्फ–मेडिकेशन की प्रवृत्ति ने भी इस संकट को बढ़ाया है। इस संकट का एक पहलू यह भी है कि कुछ चिकित्सकों में भी जरूरत से ज्यादा दवाइयां लिखने और ज्यादा पैसे वसूलने की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऐसी गलत प्रथाओं ने मेडिकल सिस्टम के प्रति लोगों में अविश्वास भी पैदा किया है। वहीं गरीबी के चलते पैसे की तंगी, सांस्कृतिक मान्यताओं और केमिस्टों के अनौपचारिक डॉक्टर के तौर पर बेरोकटोक काम करने से भी इस समस्या को बढ़ावा मिला है। अकसर यह महसूस किया जाता है कि देश की पूरी हेल्थकेयर श्रृंखला में पेशागत आचार–संहिता की नितांत कमी है। वहीं दूसरी ओर नियामक संस्थाओं की सख्त निगरानी पूरी तरह नदारद नजर आती है। सही मायने में प्रभावी बदलावों के लिये प्रोटोकॉल में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत होगी। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का व्यवहार नैतिक और जिम्मेदार होना है। निश्चय ही आज के समय में यह बेहद गंभीर चुनौती है क्योंकि इस वर्ग में अंधा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति लगातार अनियंत्रित होती नजर आ रही है। जिसके चलते कमजोर वर्ग से आने वाले मरीज खुद ही बीमारी का अंदाजा लगाने और डॉक्टर की सलाह के बिना इलाज करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। जब तक रोग बेहद गंभीर स्थिति में न पहुंच जाए, तब तक मरीज डॉक्टर के पास जाने से बचने की कोशिश करते हैं। वास्तव में किसी रोगी के उपचार के लिये लिखी गई दवाइयों की सख्ती से जांच करने की जरूरत है।

कागज़ी आंकड़ों और राशन की कतार के बीच: कहाँ खड़ा है आखिरी आदमी?

(लेखक – दिलीप कुमार पाठक)

(25 सितम्बर अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती)

समाचार माध्यमों में अक्सर बड़े नीतिगत बदलावों और कॉर्पोरेट जगत की हलचलों को प्रमुखता मिलती है, लेकिन 25 सितंबर का यह दिन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में देश के उस गरीब नागरिक को रखें, जो मुख्यधारा से कटा हुआ है। यह दिन सरकारों और अफ़सरशाही के लिए अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि व्यवस्थागत कमियों को दूर करने और जवाबदेही तय करने का अवसर है।

हर साल 25 सितंबर को देश में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू किए गए इस दिवस का एक प्रशासनिक और सामाजिक लक्ष्य समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना है। 2014 में जब केंद्र सरकार ने इस दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी, तब उद्देश्य यही था कि विकास की नीतियां केवल शहरी और संपन्न वर्ग तक सीमित न रहें, बल्कि देश के सुदूर गांवों और वंचित तबकों तक पहुंचे। लेकिन आज इस व्यवस्थागत सफर के एक दशक से अधिक समय बाद, यह आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है कि हमारी योजनाएं ज़मीन पर कितनी प्रभावी साबित हुई हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन किसी जटिल आर्थिक सिद्धांत पर आधारित नहीं था, बल्कि वह बेहद व्यावहारिक था। उनका मानना था कि किसी भी कल्याणकारी राज्य की सफलता का पैमाना उसकी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर या बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हो सकता। विकास का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि देश के सबसे गरीब और संसाधनहीन नागरिक को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं। आज जब भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तब इस अंत्योदय दर्शन की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। यदि हम विकास के नीतिगत और सांख्यिकीय ढांचे को देखें, तो सरकार ने कई मोर्चों पर बजटीय आवंटन और ढांचागत सुधार किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक देश के लगभग 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं के 92 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से पीएम–यशस्वी और पीएम–दक्ष जैसी कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विमुक्त समुदायों के युवाओं को सीधे तकनीकी प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम प्रशासनिक प्रयासों और आंकड़ों के बावजूद, ग्राउंड ज़ीरो यानी ज़मीनी हकीकत में चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं। नीतियों का कागज़ पर उत्कृष्ट होना एक बात है, लेकिन उनका अंतिम लाभार्थी तक बिना किसी रुकावट के पहुँचना दूसरी बात है। आज भी देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी खामियों, जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन न होने के कारण गरीबों को राशन के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।

प्रशासनिक बिचौलियों और स्थानीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार आज भी उस आख़िरी आदमी के अधिकारों का हनन कर रहा है। मुफ्त राशन या सब्सिडी तात्कालिक राहत के लिए अनिवार्य हो सकती हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं। असली अंत्योदय तब सिद्ध होगा जब देश के अंतिम व्यक्ति को खैरात के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गरिमापूर्ण रोजगार के समान अवसर मिलेंगे। जब तक हम अपने मानव संसाधन को केवल उपभोक्ता बनाए रखने के बजाय उत्पादक नहीं बनाएंगे, तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा। समाचार माध्यमों में अक्सर बड़े नीतिगत बदलावों और कॉर्पोरेट जगत की हलचलों को प्रमुखता मिलती है, लेकिन 25 सितंबर का यह दिन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में देश के उस गरीब नागरिक को रखें, जो मुख्यधारा से कटा हुआ है। यह दिन सरकारों और अफ़सरशाही के लिए अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि व्यवस्थागत कमियों को दूर करने और जवाबदेही तय करने का अवसर है। देश का वास्तविक विकास उसी दिन सुनिश्चित होगा, जब अंत्योदय केवल एक वार्षिक आयोजन या राजनीतिक नारा न रहकर प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली का स्थायी हिस्सा बन जाएगा।

(लेखक स्तंभकार हैं)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

वाणी का शरीर पर प्रभाव

–प्रसन्नता से होता है शरीर पुष्ट एवं प्रोध से होती है हानी

मानव शरीर में अनेक ग्रंथियां होती हैं,पियूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, उससे 12 प्रकार के रस निकलते है, जो भावनाओं से विशेष प्रभावित होती हैं। जब व्यक्ति प्रसन्नचित होता है, तो इन ग्रनथियों से विशेष प्रकार के रस बहने लगते है, जिससे शरीर पुष्ट होने लगता है, बुद्धि विकसित होती है, रक्त गति सामान्य रहती है। जब मनुष्य अधिक बोलता है, तो रक्त की गति अनावश्यक प्रभावित होती है। जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,खून के थक्के बनने लगते है । इसी प्रकार प्रोध अधिक करने से खून का बहाव कम हो जाता है, खून जमने की शक्ति बढ़ जाने से मृत्यू भी संभव है। अपने जीवन में ज्यादा बोलना अभिशाप हो सकता है। अधिक बोलने से पाचन क्रिया पर गलत प्रभाव पड़ता है, शरीर की अधिक शक्ति खर्च होती है, पेट की माँसपेशियां खिचने लगती है, पाचन रस ग्रंथियों से नही निकलता, शरीर में विटामिन, खनिज तत्व एवं हार्मोन्स की कमी हो जाती हैं। शरीर रोगी हो जाता है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, अत-वाणी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हर प्राणी को अपना जीवन झूठा, बनावटी, जोर जोर से बोलने बाला ना बना कर शांत चित बनाना चाहिए ।

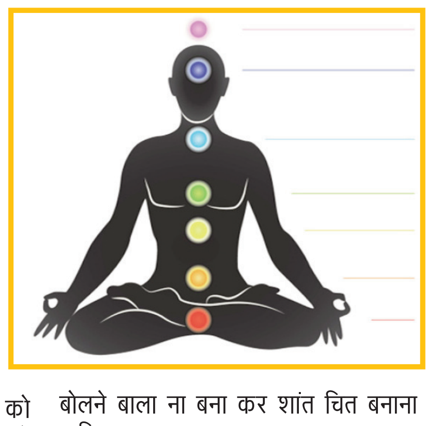

टीएमसी के 20 बागी सांसद, तारीख पर तारीख का खेल?

(लेखक – सनत जैन)

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा जताई है, जल्द से जल्द इस मामले में स्पीकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा तय नहीं की। यह जरूर कहा, सुप्रीम कोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकती है। जल्द से जल्द मामला निपटाने की याद जरूर दिला सकती है। ऐसी याद दिलाने का कोई असर नहीं होता है। जब भय ही नहीं होगा, तो इस तरह के निर्देश का कभी पालन भी नहीं होगा। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटिस के बावजूद भी सांसदों ने कोई जवाब नहीं दिया। सलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष नोटिस जारी कर चुके हैं। वहीं बाकी सांसदों कि ओर से पेश वकीलों ने कहा, वह चार सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब दाखिल कर देंगे। कुल मिलाकर तारीख पर तारीख का यह खेल कोई नई बात नहीं है। दल–बदल कानून के अंतर्गत दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों की अयोग्यता को लेकर महाराष्ट्र से जो खेल शुरू हुआ था, सारे देश ने उसका हश्र देख लिया है। महाराष्ट्र के मामले में भी इसी तरह से तारीख पर तारीख का खेल चला था। विधानसभा अध्यक्ष ने कई महीनों तक फाइल को अपने पास दबा के रखा था। इसी बीच चुनाव आयोग भी एक–दूसरे की मदद कर रहे थे। चुनाव आयोग, सुप्रीमकोर्ट और विधानसभा/ लोकसभा अध्यक्ष के बीच में इसी तरह का खेल कई बार पहले भी खेला जा चुका है। समय निकलने के बाद इस तरह की याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह फैसला इसी तरह का हुआ, जब आदमी मर गया, तब उसके मामले में फैसला आया। उसके मरने के कारण फाइल बंद कर दी गई? लेकिन उसे समय पर न्याय नहीं मिला। महाराष्ट्र की लंबित दल–बदल याचिकाओं पर कानूनी बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यह धारणा बनती चली जा रही है। दलबदल जैसे संवेदनशील मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विवाद और दबाव से बचने के लिए तारीख पर तारीख का खेल खेलते हैं। विशेष रूप से उन मामलों में जहां लाभान्वित पक्ष भाजपा हो। तेलंगाना में एक विधायक के दलबदल मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने फटाफट फैसला सुना दिया है। विधायक की सदस्यता निरस्त कर दी है। वहीं पिछले 4 महीने से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के यहां जो याचिका दायर कर कार्यवाही की मांग की थी। मानसून सत्र भी निकल गया। लोकसभा अध्यक्ष के यहां से तारीख पर तारीख का खेल खेला जा रहा है। इससे व्यथित होकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख पर तारीख का खेल खेलना शुरू कर दिया है। फैसला कब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल भी इस मामले में सरकार की ओर से खड़े होकर बागी सांसदों और विधायकों की मदद कर रहे हैं। दल–बदल कानून को लेकर पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी जब कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, दलबदलू वहां विधायक और मंत्री बने रहे। दोबारा चुनाव लड़ लिया। फैसला अभी तक नहीं आया। रही सही कसर चुनाव आयोग ने पूरी कर दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिवसेना का चुनाव चिन्ह सीज करके नया चुनाव चिन्ह दे दिया। कुछ इसी तरह की कार्यवाही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में की है। जिसके कारण देश में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जो विश्वास आमजनों के मन में था, वह विश्वास खत्म होता जा रहा है। अब यह धारणा बनने लगी है, न्यायपालिका सहित अन्य संवैधानिक संस्था जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। सब सत्तारुड दल भाजपा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, या तो मामले को टालते हैं या ऐसा निर्णय देते हैं, जिससे क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राकपा के साथ यही हुआ। अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ यही सब हो रहा है। आम आदमी और राजनीतिक दल इस खेल को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। जिसके कारण सड़कों पर आकर विरोध करना और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बन रहा है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सभी संवैधानिक संस्थाओं और सभी सरकारों के कार्यों की समीक्षा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान के अनुसार यदि समय पर सुनवाई नहीं करती हैं या समय पर निर्णय नहीं करती हैं। जबकि उन्हें समीक्षा करने के बाद आदेश देने का पूर्ण अधिकार है। पिछले कुछ वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं के साथ–साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तारीख पर तारीख का खेल खेला जा रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शेयर बाजार में हाहाकार

सेंसेक्स 1247, निफ्टी 383 अंक गिरा

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। इससे एक ही दिनों में निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गये। आज जब सभी क्षेत्रों में हुई भारी बिकवाली के चलते इक्विटी इंडेक्स नीचे आया। दिन भर के कारोबरर के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,247.71 अंक नीचे आकर 73,580.54 पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 383.70 अंक खिसककर 23,063.10 पर बंद हुआ।बाजार की इस चौतरफा गिरावट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीएसई पर कुल 4,573 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से केवल 1,476 शेयरों में ही बढ़त दर्ज की गई, जबकि 2,878 शेयरों में गिरावट आई और 219 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिकवाली का दबाव व्यापक था।

निफ्टी पर सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और इंटरग्लोब एविएशन प्रमुख रहे, जिन्होंने सूचकांक को नीचे खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, इस विपरीत माहौल में सिप्ला और एनटीपीस जैसे कुछ ही शेयरों में मामूली बढ़त देखने को मिली, जो बाजार के निराशाजनक रुख को और पुख्ता करता है।निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स गिरकर सबसे अधिक प्रभावित हुआ, उसके बाद निफ्टी मेटल , निफ्टी बैंक, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी ऑटो निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी पीएयू बैंक , निफ्टी एनर्जी 1.2त्न और निफ्टी एफएमसीजी नीचे आए। व्यापक बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 2 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.5 फीसदी गिरा, जो बताता है कि छोटे और झोले शेयरों में भी भारी बिकवाली हुई।इस तेज गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार थे। वैश्विक स्तर पर, अमेरिका में बिजनेस एक्टिविटी का पांच साल से अधिक समय में अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंचना एक चिंता का कारण बना। नए ऑर्डरों में उछाल के कारण यह डेटा बेंचमार्क 10-साल के अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड को 2007 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर ले गया, जिससे बाजार में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गईं।

इसके अलावा, अमेरिका-ईरान राजनयिक संबंधों को लेकर फिर से बनी अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित किया।

अदाणी समूह का पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश

कोलकाता ।

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 2035 तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की बड़ी घोषणा की। उन्होंने यह ऐलान न्यू टाउन, कोलकाता में 2,000 बिस्तरों वाले अदाणी आरोग्य मंदिर अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम में किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। अदाणी ने बताया कि इस अस्पताल परियोजना पर 4,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे लगभग 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योगपति ने कहा कि समूह का यह विशाल निवेश बंदरगाह, लॉजिस्टिक, बिजली, सड़क और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रित होगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

क्रूड के 100-115 प्रति बैरल होने के बावजूद सरकार ने की पुष्टि

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज संकट के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100-115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद, भारत में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जिससे आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हाल दाम स्थिर रहने की उम्मीद- सरकारी सूत्रों ने बिजनेस टुडे को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के ऊंचे दाम बने रहने के बावजूद, फिलहाल घरेलू ईंधन की कीमतों में वृद्धि की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार लगातार वैश्विक तेल बाजार पर पैनी नजर बनाए हुए है। यह खबर उन आम लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जो पिछले कई महीनों में लगातार हुई मूल्य वृद्धि से प्रभावित हुए थे। हालांकि, यह समझना गलत होगा कि दाम कभी नहीं बढ़ेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कच्चे तेल की लागत और ईंधन आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करेंगी। सरकार का मुख्य जोर होर्मुज मार्ग से तेल आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने पर है। इसके लिए, जरूरत पड़ने पर तेल कंपनियों को आर्थिक मदद भी दी जा सकती है ताकि कच्चे तेल की लागत बढ़ने का सीधा बोझ ग्राहकों पर न पड़े और ईंधन की सप्लाई लगातार जारी रहे।

सोने और चांदी के भाव में गिरावट

सोना 1,52,090 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,36,080 रुपए प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली ।

भारतीय बाजारों में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1,500 रुपये से अधिक सस्ता होकर 1,52,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी में भी 3,800 रुपये से ज्यादा की कमी के साथ 2,36,080 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार हुआ। यह गिरावट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में देखी गई, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व के सख्त मौद्रिक नीति के संकेत हैं। इंडिया एमसीएक्स पर भी सोने का भाव 1,51,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,36,085 रुपये प्रति किलो पर दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुमूल्य धातुओं पर दबाव दिखा, जहां सोना 1.43 फीसदी टूटकर 4,277.29 डॉलर प्रति औंस और चांदी 3.20 फीसदी गिरकर 63.88 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव दिल्ली में 1,51,550 रुपये और मुंबई में 1,51,810 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी दिल्ली में 2,35,240 रुपये और मुंबई में 2,35,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिकी। इस गिरावट की मुख्य वजह डॉलर की मजबूती है, जो जुलाई के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के सख्त मौद्रिक नीति संबंधी बयानों ने भी ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदों को मजबूत किया है, जिससे सोने जैसी गैर-लाभकारी संपत्तियों का आकर्षण कम हुआ है।

2 अक्टूबर को नो यूपीआई डे का ऐलान

कारोबारी 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के विरोध में

नई दिल्ली ।

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले नए शुल्क के खिलाफ देशभर के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (एफएआईवीएम) और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सहित कई प्रमुख संगठनों ने 2 अक्टूबर को नो यूपीआई डे मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत उस दिन यूपीआई से कोई लेनदेन नहीं होगा। आम जनता को कैश या कार्ड से भुगतान करना होगा। कारोबारी 2000 रुपये से अधिक के पीयर-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर 15 अक्टूबर से लगने वाले 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क का विरोध कर रहे हैं।

भारत की आर्थिक उड़ान, वैश्विक एजेंसियों ने बढ़ाया वृद्धि अनुमान

नई दिल्ली ।

इंट्रो वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार मजबूती दिखाई है। इसी का परिणाम है कि मूडीज के बाद अब एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसी वैश्विक एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1 फीसदी तक कर दिया है, जो वैश्विक भरोसे को और पुख्ता करता है। एजेंसियों ने पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में उम्मीद से बेहतर 7.8 फीसदी की आर्थिक वृद्धि, मजबूत घरेलू मांग, निवेश, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन को अनुमान बढ़ाने का प्रमुख कारण बताया है।

यह दर्शाता है कि भारत बाहरी झटकों को झेलने में अब अधिक सक्षम है। बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड सरकारी खर्च, मजबूत घरेलू खपत और लचीला निर्यात तंत्र भारत को जी-20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखेगा।

घरेलू खपत पर निर्भरता के चलते मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बरकरार रही है और मांग लगातार बनी हुई है। सरकारी पूंजीगत व्यय के साथ-साथ निजी निवेश में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है।

यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और स्थिरता का स्पष्ट संकेत है।

एफएसएसएआई का ई-कॉमर्स के दिग्गजों पर शिकंजा

गलत ब्रांडिंग, भ्रामक दावों और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर कार्रवाई

नई दिल्ली ।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने गलत ब्रांडिंग, भ्रामक दावों और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री सहित खाद्य सुरक्षा कानूनों के गंभीर उल्लंघन को लेकर कई प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया शुरू की है। इन मंचों में स्विगी इंस्टामार्ट, बिगबास्केट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट इंडिया और अमेजन भी शामिल हैं। एफएसएसएआई ने अपने सोशल मीडिया मंच पर इस 'बड़ी कार्रवाई' की जानकारी देते हुए बताया कि उल्लंघन में गलत ब्रांडिंग, भ्रामक दावे और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले या प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन व बिक्री शामिल है। प्राधिकरण ने हैप्पिलो प्रीमियम डेट बाइट्स - जेस्टी ऑरेंज से जुड़े भ्रामक दावों के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट इंडिया, स्विगी इंस्टामार्ट, जेप्टो और बिगबास्केट के खिलाफ कार्रवाई की है। स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट को मिल्की मिस्ट के कुछ डेयरी उत्पादों, जैसे लो फैट क्रीम और ग्रीक योगर्ट, के भ्रामक दावों और अधूरी उत्पाद जानकारी के लिए निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अमेजन सेलर सर्विसेज, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट पर धतूरा के फल/बीज जैसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप हैं। एफएसएसएआई पिछले छह महीनों से खाद्य कारोबारियों और ई-कॉमर्स कंपनियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी जागरूक कर रहा है।

बीमा ग्राहकों के लिए खुशखबरी:आईआरडीएआई ला रहा सस्ते और पारदर्शी बीमा का दौर

नई दिल्ली ।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा पॉलिसी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए नियमों में बदलावों का प्रस्ताव किया है, जो उनके लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकते हैं। इन नए नियमों का मकसद बीमा की लागत को नियंत्रित करना, बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और गलत तरीके से पॉलिसी बेचने की शिकायतों पर लगाम लगाना है। इससे फिजूलखर्ची, मनमानी और एजेंटों के कमीशन पर भी लगाम लगेगी।

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट (ईओएम) की सीमा कम करने का सुझाव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को दो साल में अपना ईओएम ग्रोस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम (जीडीपीआई) के 15 प्रतिशत और पांच साल में 12.5 प्रतिशत तक लाना होगा। वहीं, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इसकी सीमा पांच साल में 30 से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इन कदमों से बीमा कंपनियों की फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को कम प्रीमियम के रूप में मिलेगा।

इतना ही नहीं कमीशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। अब सभी पॉलिसी के लिए एक समान कमीशन के बजाय, उत्पाद की प्रकृति, अवधि और बिक्री में लगने वाली मेहनत के आधार पर कमीशन तय होगा। इस प्रक्रिया में मनमानी कमीशन पर रोक लगेगी और एजेंटों को उत्पाद की जरूरत के हिसाब से प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के लिए, इंडिविजुअल नॉन-लिंक्ड

और लिंक्ड पॉलिसी में इंटरमीडियरी का कमीशन 5 से 20 फीसदी, जबकि एजेंटों का 6.25 से 25 फीसदी तक हो सकता है। प्योर टर्म प्लान में पहले साल इंटरमीडियरी को 25 फीसदी और एजेंट को 30 फीसदी तक कमीशन मिल सकता है।हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस के लिए भी नए कमीशन दरें प्रस्तावित हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की नई बिक्री पर डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं के लिए करीब 15 फीसदी और एजेंटों के लिए 20 फीसदी कमीशन प्रस्तावित है, जबकि रिन्यूअल पर यह क्रमशः 5 और 10 फीसदी रहेगा। वहीं, मोटर थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कमीशन शून्य रखने का प्रस्ताव है, जबकि एजेंटों को 2.5 फीसदी तक मिल सकता है।

कुल मिलाकर, आईआरडीएआई के ये प्रस्ताव बीमा क्षेत्र में ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे बीमा पॉलिसी खरीदना सस्ता, सरल और अधिक विश्वसनीय हो जाएगा।

आरडीएआई का बड़ा दांव: बीमा बेचना और खरीदना होगा ज़्यादा पारदर्शी और ग्राहक हितैषी

प्रस्तावों का लक्ष्य वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना और ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना

नई दिल्ली ।

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (आईआरडीएआई) ने बीमा वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और ग्राहक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया है। नियामक ने बुधवार को रीकैलिब्रेटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ़ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नामक एक पब्लिक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसमें बीमा वितरण संरचना, खर्च, कमीशन, बाजार आचरण और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। इन प्रस्तावित सुधारों का लक्ष्य एक कुशल और निष्पक्ष वितरण इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे ग्राहकों को बेहतर जानकारी और सुरक्षा मिल सके। आईआरडीएआई के इस प्रस्ताव से ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी, उनके भुगतान के तरीके में पारदर्शिता आएगी, अनावश्यक बंडलिंग कम होगी और गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। आईआरडीएआई का एक मुख्य प्रस्ताव बीमा वितरण संरचना को सरल बनाना है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए यह समझना आसान बनाना है कि उन्हें कौन पॉलिसी बेच रहा है और वितरण श्रृंखला में कौन से बिचौलिये शामिल हैं। इससे नियामक और परिचालन बाधाएं भी कम होंगी, जिससे बीमा वितरण में भागीदारी बढ़ेगी। ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव बीमा डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाने वाले कमीशन के खुलासे से संबंधित है। आईआरडीएआई ने प्रस्ताव दिया है कि बीमा कंपनियाँ और बड़ी वितरण कंपनियां अपनी कमीशन नीति और संरचना को सरल और समझने योग्य तरीके से सार्वजनिक करें। कुछ वाणिज्यिक पॉलिसियों में भी कमीशन की जानकारी दी जाएगी, जिससे ग्राहक वितरण लागत को समझकर सूचित निर्णय ले सकें। कमीशन ढांचे को भी उत्पाद की प्रकृति, व्यवसाय के प्रकार और बिक्री व सर्विसिंग में लगने वाले प्रयास के आधार पर पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) पर लगाम लगाने के लिए भी सख्त उपाय सुझाए गए हैं। इनमें ग्राहकों की आवश्यकताओं और उपयुक्तता का रिकॉर्ड रखना, साथ ही कमीशन की परिभाषा में सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भुगतानों को शामिल करना शामिल है।

रुपया गिरावट पर बंद

नई दिल्ली ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को भारतीय रुपया 23 पैसे की गिरावट के साथ ही 95.96 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 11 पैसे टूटकर 95.84 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल और डॉलर दोनों मजबूत हुए, जिसका असर रुपये पर पड़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, विदेशी पूंजी का प्रवाह घरेलू मुद्रा को सहारा देने में विफल रहा क्योंकि घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव और अमेरिकी मुद्रा में मजबूती बनी हुई है। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.84 प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती कारोबार में दबाव में रहा। यह पिछले बंद भाव से 11 पैसे की गिरावट है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे टूटकर 95.73 पर बंद हुआ था। इससे एक दिन पहले इसमें 16 पैसे की मजबूती आई थी। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 फीसदी बढ़कर 100.87 पर कारोबार कर रहा था।

एफडी में निवेश अब और पारदर्शी, आरबीआई के बदले नियम 1 अक्टूबर से लागू

एक ही बैंक की सभी शाखाओं में समान अवधि के लिए ब्याज दरें होंगी एक समान

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य एफडी की ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों तक सही जानकारी की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत, एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में समान अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरें एक जैसी होंगी, जिससे स्थान-आधारित भिन्नता खत्म होगी। इसके अलावा बैंकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी एफडी योजनाओं और उनकी ब्याज दरों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक की बल्क डिपॉजिट के लिए भी, ब्याज दरों को बैंक की वेबसाइट पर रोजाना सुबह 10-10 बजे तक अपडेट करना

होगा। मौजूदा एफडी पर इन बदलावों का तत्काल कोई असर नहीं होगा; वे अपनी वर्तमान शर्तों पर ही चलती रहेंगी।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्धविराम को दो माह का विस्तार

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता कम करने की दिशा में कदम

वाशिंगटन ।

अमेरिका और चीन ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाले अपने व्यापार युद्धविराम को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़े आर्थिक समझौते की दिशा में काम करने के लिए इस अवधि को 10 जनवरी तक विस्तारित करने की घोषणा की। यह कदम चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के वाशिंगटन पहुंचने के ठीक बाद उठाया गया है, जिससे वैश्विक बाजारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले साल अक्टूबर में हुए बुसान समझौते के तहत एक साल का यह व्यापार युद्धविराम नवंबर में समाप्त होने वाला था। बेसेंट ने स्थानीय न्यूज चैनल को बताया कि अब इसे 10 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा, जिससे दोनों देशों को एक संभावित बड़े समझौते पर काम करने का अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि, चीन के अधिकारियों ने अभी तक इस विस्तार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बेसेंट ने जनवरी तक बड़े आर्थिक पैकेज की संभावना जताई है, लेकिन मौजूदा समझौते की अवधि को आगे बढ़ाने का विकल्प भी खुला है। अमेरिका चाहता है कि चीन अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से लागू करे। राष्ट्रपति ट्रंप और शी चिनफिंग की वाशिंगटन में महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं, जिनमें व्यापार शुल्क, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस विस्तार से दोनों देशों को इन जटिल वार्ताओं के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

बाजार में एनएसई का दबदबा, शीर्ष 10 मूल्यवान कंपनियों में बनाई जगह

मामूली बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ एनएसई दिन के कारोबार में 1,878 रुपए तक पहुंचा

नई दिल्ली ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने गुरुवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत करते हुए बाजार मूल्यांकन के लिहाज से देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपनी जगह बना ली। कारोबार के दौरान एनएसई के शेयर पांच प्रतिशत से अधिक उछले, जो इसके मजबूत प्रदर्शन का संकेत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के शेयरों ने गुरुवार को कारोबार के दौरान पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की, जिससे इसका बाजार मूल्यांकन 4,54,966.88 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ, एनएसई बाजार मूल्यांकन के मामले में भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में शामिल हो गया है। बीएसई पर एनएसई के शेयर 1,800 रुपए पर सूचीबद्ध हुए, जो इसके निर्गम मूल्य 1,785 रुपए से 0.84 प्रतिशत अधिक था। कारोबार के दौरान, शेयरों में 5.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई और यह 1,878 रुपए के स्तर पर पहुंच गया, जिसने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया। एनएसई ने बाजार मूल्यांकन के इस क्रम में दसवां स्थान हासिल किया है, और उसने 4,54,845.62 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर और 4,46,985.57 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण वाली सन फार्मा जैसी स्थापित कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, इसके प्रतिद्वंद्वी बीएसई का बाजार मूल्यांकन 1,31,946.42 करोड़ रुपये रहा। इससे पहले, एनएसई का 22,569 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सोमवार को बोली के अंतिम दिन लगभग छह गुना अभिदान प्राप्त कर चुका था, जिसमें संस्थागत निवेशकों की जबरदस्त मांग देखी गई। यह आईपीओ 2024 में हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपए के आईपीओ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम साबित हुआ है।

इसने 2022 में आए एलआईसी के 21,000 करोड़ रुपएके आईपीओ को भी पीछे छोड़ दिया, जो इसकी बढ़ती बाजार शक्ति और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

अबेकस म्यूचुअल फंड को मिली सेबी की बड़ी मंजूरी

फोक्कस के साथ एसआईएफ सेगमेंट में करेगा प्रवेश

नई दिल्ली ।

निवेश क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अबेकस म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया कि सेबी ने 28 अगस्त, 2026 को यह मंजूरी दी है। अबेकस अपने एसआईएफ को फोक्कस ब्रांड नाम से बाजार में उतारेगा, जिससे उसे निवेशकों के लिए विविध और अनूठी निवेश रणनीतियाँ पेश करने का नया अवसर मिलेगा। अबेकस ने बताया कि फोक्कस ब्रांड के तहत वह इक्विटी, डेट और हाइब्रिड जैसी विभिन्न श्रेणियों में निवेश रणनीतियां पेश करेगा। ये रणनीतियां लागू नियमों और आवश्यक मंजूरियों को पूरा करने के अधीन होंगी। कंपनी का उद्देश्य इन एसआईएफ के माध्यम से अपनी मौजूदा शोध-आधारित निवेश रणनीति और अनुशासित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को एक नए, लचीले ढांचे के साथ एकीकृत करना है। सेबी ने 1 अप्रैल, 2025 से एसआईएफ ढांचे को लागू किया था। यह ढांचा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अलग-अलग निवेश रणनीतियां पेश करने की अनुमति देता है, साथ ही म्यूचुअल फंड पर लागू नियामकीय निगरानी और निवेशक सुरक्षा सिद्धांतों को भी बनाए रखता है। अबेकस ने स्पष्ट किया कि इन रणनीतियों के निवेश उद्देश्यों, एसेट एलोकेशन, जोखिम-कारकों और लॉन्च की समयसीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी नियामकीय फाइलिंग पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। अबेकस के एक प्रमुख अधिकारी ने इस कदम को कंपनी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि एआईएफ, पीएमएस, म्युचुअल फंड और अब एसआईएफ - इन सभी सेगमेंट में हमारा उद्देश्य हमेशा निवेशकों के लिए सार्थक अवसरों की पहचान करना रहा है।÷ सिंघानिया ने जोर दिया कि एसआईएफ ढांचा विभिन्न निवेश रणनीतियों को अपनाने में लचीलापन देता है, जिससे कंपनी अपनी निवेश सोच पर कायम रहते हुए निवेशकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकेगी और विभिन्न बाजार चक्रों में अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए कब तक खेलेंगे ! भविष्य पर दिया बड़ा बयान

लिस्बन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर स्थिति साफ कर दी है। 41 वर्षीय स्टार फुटबॉलर ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय टीम को उनकी जरूरत है, वह खेलते रहेंगे। हालांकि, जिस दिन उन्हें लगेगा कि वह टीम के लिए योगदान नहीं दे पा रहे हैं या टीम उन्हें नहीं चाहती, वह सबसे पहले खुद टीम छोड़ देंगे।

रोनाल्डो ने जुलाई में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में पुर्तगाल के स्पेन से बाहर होने के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय भविष्य की पुष्टि नहीं की थी। हालांकि, नए मुख्य कोच जॉर्ज जीसस की पहली पुर्तगाल टीम में उन्हें शामिल किए जाने से साफ हो गया कि वह अभी राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध हैं।

'जब नहीं चाहेंगे, सबसे पहले मैं चला जाऊंगा'

वेल्स के खिलाफ मुकाबले से पहले रोनाल्डो ने अपने भविष्य को लेकर कहा, 'जब भी वे कहेंगे कि वे मुझे राष्ट्रीय टीम में नहीं चाहते, मैं सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति बनूंगा। जब मुझे लगेगा कि मैं टीम में कुछ नहीं जोड़ रहा हूं या माहौल खराब कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले चला जाऊंगा। मैं अपना सूटकेस उठाऊंगा और चला जाऊंगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'पुर्तगाल के लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से मैं अभी यहां हूं। सिर्फ आंकड़ों को देखिए, मुझे यकीन है कि आप कुछ गणना कर सकते हैं। मैं अभी भी अच्छा कर रहा हूं। जिस दिन उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मैं हमेशा इस महासंघ का नंबर एक प्रशंसक रहूंगा।'

विश्व कप के बाद संन्यास पर किया था विचार

रोनाल्डो ने माना कि विश्व कप से बाहर होने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से हटने के बारे में विचार किया था। हालांकि, पुर्तगाल के राष्ट्रपति पेड्रो प्रोएंका और कोच जॉर्ज जीसस के साथ बातचीत के बाद उन्होंने खेलना जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'हां, मैंने ऐसा किया था। बेशक, मैं हमेशा अपने फैसलों, अपने भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचता रहता हूं। मैं सोचने वाला इंसान हूं, आपको सोचना पड़ता है। इसी वजह से आप मुझे अब यहां देख रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं जारी रखूंगा।' रोनाल्डो ने यह भी कहा कि वह सिर्फ गोल करने के लिए नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों की मदद करके भी टीम में योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे अब भी विश्वास है कि मैं राष्ट्रीय टीम को वह हासिल करने में मदद कर सकता हूं जो वह चाहती है। मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रीय टीम को अपना समर्थन दे सकता हूं, सिर्फ गोल के जरिए नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी।'

मुक्केबाज परवीन पदक पक्का करने से एक जीत दूर, क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

नागोया। भारतीय मुक्केबाजों के लिए एशियन गेम्स का पांचवां दिन मिलाजुला रहा। परवीन ने महिला 65 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का करने के मजबूत कदम बढ़ाए, वहीं साक्षी और सुमित को अपने-अपने बाउट में हार का सामना करना पड़ा। परवीन को तजाकिस्तान की मलिका नोजिमोवा से वॉकओवर मिला जिससे वह अगले दौर में पहुंच गईं। परवीन पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। मुक्केबाजी में सेमीफाइनल में पहुंचने पर पदक पक्का हो जाता है।

भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी महिलाओं के 51 किलो वर्ग में कजाखस्तान की अलुआ बाल्कीबेकोवा से प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं। हरियाणा की 26 वर्ष की साक्षी ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन यहां वह लय कायम नहीं रख सकीं। पहले दौर के बाद कजाखस्तान की मुक्केबाज 3-2 से आगे थी। दूसरे दौर में साक्षी ने आक्रामकता दिखाई लेकिन बाल्कीबेकोवा ने 3-2 से फिर बढ़त बनाई। आखिरी दौर में साक्षी वापसी करने में नाकाम रही।

चोट के कारण बाहर हुए सुमित

इससे पहले सुमित पुरुषों के 70 किलो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इराक के अल सारे अली के खिलाफ चोट के कारण बाहर हो गए। हरियाणा के 23 वर्ष के सुमित पहले दो दौर में आगे थे, लेकिन

तीसरे दौर में एक मुक्के से बचने के प्रयास में उन्हें घुटने में चोट लगी और वह गिर गए। इसके बाद वह आगे खेल नहीं सके और रैफरी ने मुकाबला रोककर विरोधी को विजेता घोषित कर दिया। सुमित ने पहले मुकाबले में थाईलैंड के बुंजोंग सिनसिरी को 5-0 से हराया था।

भारतीय हॉकी टीम की द. कोरिया पर सबसे बड़ी जीत

आइची नागोया। पुरुष हॉकी में पूल-ए के मैच में भारतीय हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 8-2 से हरा दिया। भारत ने कोरिया पर हाफटाइम तक 5-0 की बढ़त बना ली थी। भारत के लिए शिलानंद लाकरा ने चौथे मिनट, सुखजीत सिंह ने नौवें मिनट में गोल दागे। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 11वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दाग भारत को 3-0 से आगे कर दिया। इसके एक मिनट बाद अभिषेक ने गोल दागा। फिर दिलप्रीत सिंह ने 26वें मिनट में गोल दाग भारत को 5-0 से आगे कर दिया।

तीसरे क्वार्टर में भारत ने दो और गोल दागे, जबकि कोरिया की ओर से भी पहला गोल हुआ। भारत की ओर से दिलप्रीत ने 32वें मिनट में अपना दूसरा गोल और अभिषेक ने 38वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा। दक्षिण कोरिया की ओर से एकमात्र गोल किम जैहो ने 42वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर तक भारत 7-1 से आगे थे।फिर चौथे क्वार्टर में दक्षिण कोरिया की ओर से किम योंगबोक ने 52वें मिनट में गोल दाग स्कोर 7-2 कर दिया। वहीं, रजिंदर सिंह ने 60वें मिनट में गोल दागा और स्कोर 8-2 कर दिया। आखिर तक यही स्कोरलाइन रहा और भारत ने जीत हासिल की। अब पूल स्टेज में ही भारत का सामना जापान से होगा। भारत की नजरें एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल करने पर हैं।

कराटे में 100 खिलाड़ियों ने दिखाया दम, 10 ने जीते पदक

हाथरस। हाथरस के मेला श्रीदाऊजी महाराज के उपलक्ष्य में वर्ल्ड बुडो शोटोर्यू कराटे महासंघ के बैनर तले सातवीं श्री दाऊजी ओपन कराटे कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते।

उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कुंवर रत्नेश रत्न ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन लाते हैं। जो खिलाड़ी जीते हैं, उन्हें बधाई और जो हारे हैं, वे निराश न होकर और अधिक मेहनत करें। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनुराग अग्निहोत्री एडवोकेट और उप जिला क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश यादव उपस्थित रहे। संचालन पूर्व डीजीसी क्रिमिनल एडवोकेट वतन सिंह ने किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉ. रामबाबू हरित रहे।

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामवीर सिंह भैयाजी, जिला पंचायत सदस्य प्रभा सिंह, अश्वनी सिंह, एडवोकेट रतन सिंह और महासंघ के अध्यक्ष व मुख्य प्रशिक्षक शिहान एमएस सामुराई ने संयुक्त रूप से विजयी प्रतिभागियों को पदक पहनाकर पुरस्कृत किया। अतिथियों को भी स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में हाथरस के विनायक इंटरनेशनल स्कूल, बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सेठ हरचरनदास कन्या इंटर कॉलेज, अलीगढ़ के आरसीएमडी इंटरनेशनल स्कूल के अलावा आगरा, मथुरा, टूंडला और अलीगढ़ के विभिन्न विद्यालयों के 100 बालक-बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान रेफरी पैनल के चीफ नितिन सोलंकी, विजेंद्र माहौर, रूबी कुमारी, जज हिमेश डेविड, विशाल ढकराल, सुबह सिंह और दीपक राज व सलमान आदि मौजूद रहे।

स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में आमने-सामने होंगी अनाहत और तन्वी, चार भारतीयों को भी मिली जीत

नागोया अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, अभय सिंह और वीर चोटरानी ने एशियन गेम्स की स्क्वाश स्पर्धा के एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार की जोड़ी मिश्रित युगल के अंतिम आठ में पहुंची। जूनियर विश्व चैंपियन और पदक की दावेदार अनाहत ने महिला एकल में सिंगापुर की वाई इयिन औ येओंग को महज 19 मिनट में 3-0 (11-4, 11-5, 11-7) से हराकर अभियान की शुरुआत की।

सेमीफाइनल में पहुंचने पर तय नहीं होगा पदक

इसके बाद तन्वी ने भी सिंगापुर की वाई यान औ येओंग को 39 मिनट में 3-1 (5-11, 11-4, 11-5, 13-11) से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इन नतीजों के साथ महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में अनाहत और तन्वी के बीच मुकाबला

तय हो गया है। पिछले एशियन गेम्स के विपरीत इस बार स्क्वाश की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का पदक पक्का नहीं होगा। कांस्य पदक के लिए सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे-चौथे स्थान का मुकाबला खेला जाएगा।

अभय सिंह का दमदार प्रदर्शन

पुरुष एकल में अभय सिंह ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के रविंदु लक्सिरी को 25 मिनट में 3-0 (11-5, 11-6, 11-0) से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में अभय का सामना मेजबान जापान के रयोउनोसुके से होगा। चोटरानी को मलयेशिया के संजय जीवा के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक घंटे नौ मिनट चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 (11-9, 8-11, 11-6, 15-17, 11-6) से जीत दर्ज कर अंतिम आठ में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उनकी भिड़ंत पाकिस्तान के इरफान मुहम्मद से होगी।

इससे पहले दिन में अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने हमवतन सूरज चंद और शमीना रियाज को सीधे गेम में हराकर मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी भारतीय जोड़ी ने ऑल-इंडियन मुकाबले में 11-7, 11-10 से जीत दर्ज की। भारतीय जोड़ी अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमीका अरिबाडो की जोड़ी से भिड़ेगी।

आज ही के दिन भारत बना था विश्व विजेता

2007 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को दी थी मात, जानें उस मैच का रोमांच

नई दिल्ली। 24 सितंबर 2007 का दिन, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग का वांडरर्स स्टेडियम एक ऐतिहासिक मैच का गवाह बना। टी20 विश्व कप इतिहास का पहला फाइनल और आमने-सामने थे क्रिकेट की दुनिया के दो घोर विरोधी भारत और पाकिस्तान। इस मैच के विजेता को सिर्फ विश्व चैंपियन नहीं बनना था, बल्कि टी20 क्रिकेट के पहले विश्व चैंपियन के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना था। यह इतिहास रचा महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली भारतीय टीम ने। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहले टी20 विश्व कप की चैंपियन होने का गौरव हासिल किया था। भारत का पाकिस्तान को हराना कोई नई बात नहीं है। भारत से हारना पाकिस्तान की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन, 19 साल पहले मिली यह जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास के चंद सबसे यादगार लम्हों में से एक है। युवा कप्तान धोनी के साथ युवा खिलाड़ियों से भरी टीम ने खिताबी जीत के बाद जब तिरंगा लहराया तो करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।यह वह समय था, जब टी20 क्रिकेट धीरे-धीरे अपने पांव जमा रहा था। भारतीय टीम को इस प्रारूप की कमजोर टीम माना जा रहा था और चैंपियन बनने की संभावना न के बराबर जताई जा रही थी, लेकिन धोनी की कप्तानी वाली टीम ने युवा जोश के साथ होश दिखाया और खिताबी जीत हासिल की। इस जीत ने टी20 क्रिकेट और उसके रोमांच को शीर्ष स्तर पर पहुंचा दिया था।

गंभीर की यादगार पारी

मैच की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत गौतम गंभीर और युसूफ पठान ने की थी। पठान आठ गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। गंभीर टिके रहे और 54 गेंदों पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 75 रनों की यादगार पारी खेलकर टीम का स्कोर पांच विकेट पर 157 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। छठे नंबर पर आकर रोहित शर्मा ने भी 16 गेंदों पर 30 रनों की बेहद अहम पारी खेली थी।158 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.3 ओवर में 152 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम ने पांच रन से जीत हासिल कर पहला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया के लिए आर. पी. सिंह और इरफान पठान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट लिए थे। जोगिंदर शर्मा ने दो और एस. श्रीसंत ने 1 विकेट लिया था। मैच अंत तक रोमांचक बना रहा था और इसका फैसला आखिरी ओवर में जाकर हुआ। भारतीय टीम को जीत के लिए एक विकेट चाहिए था और पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। पाकिस्तान का स्कोर नौ विकेट पर 145 रन था। भारतीय टीम की जीत की राह का रोड़ा मिस्बाह उल हक थे, जो पाकिस्तान को जीत के करीब लाए थे।

रोहित मेरी सोच जानते हैं, मैं उनकी सोच जानता हूं

रोहित के साथ रिश्ते पर गंभीर ने तोड़ी चुप्पीः अनबन की खबरों पर पहली बार दिया बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि रोहित के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं रहा है। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और साथ खेलने के कारण एक-दूसरे की सोच को भी अच्छी तरह समझते हैं। गंभीर और रोहित एक बार फिर भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में साथ नजर आएंगे। भारत अपने घरेलू सत्र की शुरुआत रविवार को तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से करेगा।

गंभीर ने कहा कि रोहित के साथ उनका जुड़ाव उस समय से है, जब वह खुद टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा, 'रोहित और मेरा रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं था। जब रोहित टीम में आए थे, तब मैं एक वरिष्ठ खिलाड़ी था। इसलिए रोहित और मेरा रिश्ता उसी समय से है। रोहित मुझे तब से जानते हैं। इसलिए जब आप साथ खेल चुके होते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। वह मेरी सोच जानते हैं और मैं उनकी सोच जानता हूं।'

गंभीर ने कहा कि कप्तान और कोच की सोच अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला टीम के हित में होना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'कल मेरी सोच कुछ और हो सकती है, कप्तान की सोच कुछ और हो सकती है, लेकिन आखिर में अगर जो फैसला लिया जाए वह टीम के हित में है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।'

चार कप्तानों के साथ काम करने का अनुभव

जुलाई 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच का पद संभालने के बाद गंभीर ने चार कप्तानों के साथ काम किया है। इनमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल शामिल हैं। गंभीर ने चारों के रवैये की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने टीम को खुद से ऊपर रखा।

उन्होंने कहा, 'मैंने चार कप्तानों के साथ काम किया है- रोहित, सूर्या, अब शुभमन और श्रेयस। जिन भी कप्तानों के साथ मैंने काम किया, सभी का पहला इरादा हमेशा टीम को प्राथमिकता देना रहा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे चार लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने हमेशा खुद से पहले टीम को रखा।'

श्रेयस और शुभमन की भी तारीफ

गंभीर ने कहा कि विचारधारा, सोच और खेल को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन इरादा सही होना जरूरी है। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ अपने पुराने संबंध का भी जिक्र किया। गंभीर ने बताया कि वह श्रेयस के साथ केकेआर में काम कर चुके हैं और 2018 में दिल्ली की कप्तानी उन्हें सौंपते समय भी उनकी नेतृत्व क्षमता देखी थी। उन्होंने कहा, 'मैंने श्रेयस के साथ केकेआर में काम किया है। उससे पहले, जब 2018 में मैंने दिल्ली के लिए श्रेयस को कप्तानी सौंपी थी, तो मुझे लगा था कि उनमें लीडरशिप के गुण हैं। अब, मुझे उनके साथ फिर से काम करने का मौका मिला है। शुभमन अभी युवा हैं।' शुभमन गिल को लेकर गंभीर ने कहा कि इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों में कप्तानी संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा, 'अगर आपको इंग्लैंड के दौरे पर पांच टेस्ट मैचों में कप्तानी दी जाती है और किसी को गहरे पानी में धकेल दिया जाता है तो या तो आप बहुत अच्छी तरह तैरकर बाहर निकलेंगे या डूब जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

शरीर में चलेगी खाने योग्य बैटरी, काम के बाद खुद घुल जाएगी

वाशिंगटन, एजेंसी। वैज्ञानिकों ने ऐसी बैटरी विकसित की है, जो शरीर के अंदर कुछ समय तक छोटे मेडिकल उपकरणों को बिजली देने के बाद धीरे-धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। इससे बैटरी निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका शुरुआती परीक्षण सूअरों पर सफल रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े जियोवानी ट्रैवर्सो और उनकी टीम ने इसे विकसित किया है। शोध नेचर केमिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है। बैटरी में मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। 73% अमेरिकियों को एआई से बड़े नुकसान का डर अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। 73% अमेरिकियों का मानना है कि एआई बनाने वाली कंपनियां इससे होने वाले गंभीर नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं। रॉयटर्स-इप्सोस के सर्वेक्षण में 39% लोगों ने एआई को समाज के लिए नकारात्मक बताया, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सर्वेक्षण में 55% लोगों ने एआई के विकास की रफ्तार धीमी करने को सही बताया, जबकि 13% ने इसे गलत कहा। वहीं 73% लोगों ने कहा कि दुनिया में एआई की दौड़ में आगे रहने से ज्यादा जरूरी इसका सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

क्रैश फॉर कैश घोटाले में भारतीय मूल के पूर्व ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को जेल

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक पूर्व पुलिस अधिकारी को क्रैश फॉर कैश घोटाले में भूमिका के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद चार साल और पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इस घोटाले में चोट लगने के झूठे दावे करके पैसे ऐंठे जाते थे। 42 साल का कुलदीप सिंह मेट्रोपॉलिटन पुलिस में अधिकारी था। तब वह एक ऐसे गिरोह में शामिल हुआ जो गाड़ियों की पूर्वनिर्धारित टक्कर करवाता था और बीमा कंपनियों से मुआवजे के लिए झूठे दावे करता था। कुलदीप ने इस साल की शुरुआत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसे पांच साल के लिए कंपनी डायरेक्टर बनने से भी रोक दिया गया।

स्कूल गोलीबारी मामला : ओपनएआई और सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिग्गज कंपनी ओपनएआई और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन के खिलाफ अमेरिकी संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी फरवरी माह में देश के सबसे भीषण स्कूल गोलीबारी कांडों में से एक को अंजाम देने वाली 18 वर्षीय हमलावर की हिंसक चैटजीपीटी गतिविधियों के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सचेत करने में पूरी तरह विफल रही। सैन फ्रांसिस्को स्थित फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर मुकदमे के अनुसार, ओपनएआई की ह्यूमन रिव्यू टीम द्वारा चिन्हित किए जाने के बावजूद कंपनी ने हमलावर की संदेहास्पद चैट के बारे में सुरक्षा अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी।

श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर किए थे बम धमाके : कोर्ट ने 15 आरोपियों को दी 220 साल की सजा, पांच साल चला केस

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका के 2019 ईस्टर संडे बम धमाकों के मामले में करीब पांच साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने 24 आरोपियों में से 15 को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 220 साल के कठोर कारावास की सजा दी। नौ आरोपियों को बरी किया गया। मामले में 2,309 अभियोजन गवाहों ने गवाही दी। हमलों के बाद आतंकवादी साजिश के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र की नाकामी को लेकर तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल उठे थे। कोलंबो परमानेंट हाई कोर्ट ट्रायल-एट-बार की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में सिलसिलेवार आत्मघाती धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। स्थानीय इस्लामिक चरमपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात से जुड़े नौ आत्मघाती हमलावरों ने तीन कैथोलिक चर्चों और तीन लग्जरी होटलों को निशाना बनाया था। इन हमलों में करीब 270 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 11 भारतीय भी शामिल थे। 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। संगठन के ढ्ढस्ढ्ढस् से जुड़े होने की बात सामने आई थी। कोलंबो परमानेंट हाई कोर्ट ट्रायल-एट-बार ने 15 दोषियों को 220-220 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

ट्रंप ने ग्रीनलैंड रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन ने एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत 1951 के समझौते को अपडेट किया गया है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया गया है। ट्रंप ने इस समझौते को लंबी कोशिशों का नतीजा बताया और कहा कि इससे अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। ट्रंप ने तीनों देशों के बीच हुए समझौते पर दस्तखत करने के कार्यक्रम में कहा, 'हमारे रिश्ते बहुत शानदार और सुरक्षित होंगे, और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इस पर काफी समय से काम चल रहा था। कुछ लोग सच में यह समझौता करना चाहते थे लेकिन कभी हो नहीं पाया, पर अब हम इसे पूरा कर रहे हैं।' ट्रंप ने कहा कि यह समझौता 'यूरोप, अमेरिका और सभी के लिए बहुत बढ़िया' होगा और ग्रीनलैंड के लिए तो 'अद्भुत' साबित होगा।

फ्रेडरिकसेन ने इस समझौते को अमेरिका के साथ डेनमार्क के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग में एक अहम पड़ाव बताया। उन्होंने कहा, '75 साल पहले, हमने ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था। आज, हम उससे भी बड़ा और बेहतर समझौता कर रहे हैं, एक ऐसा समझौता जो हमेशा कायम रहेगा। '

डेनमार्क की नेता ने कहा कि इस समझौते से सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता मजबूत होगी और साथ ही विरोधी ताकतों को ग्रीनलैंड में पैर जमाने से रोका जा सकेगा। फ्रेडरिकसेन ने कहा, 'हम यह पक्का कर रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड पर कोई नियंत्रण या बड़ा असर डालने की इजाजत न मिले। और हम यह भी पक्का कर रहे हैं कि आर्कटिक में एक ही समय में हमारे और सहयोगी देश भी मौजूद रहें।' उन्होंने कहा कि इस समझौते में ग्रीनलैंड और नॉर्थ अटलांटिक संधि वाले इलाके की सुरक्षा में अमेरिका के ऐतिहासिक और जारी योगदान को मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि इसमें डेनमार्क साम्राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और ग्रीनलैंड के आत्म-निर्णय के अधिकार का भी सम्मान किया गया है।

फ्रेडरिकसेन ने इस समझौते को भू-राजनीतिक तनाव के इस दौर में नाटो को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, 'अगर हम सहयोगी देशों के तौर पर बंट जाते हैं, तो हम अपने दुश्मनों की मदद करते हैं। हम ऐसा होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नीलसन ने कहा कि इस समझौते से 1951 का रक्षा समझौता '2026 के दौर' के हिसाब से अपडेट हो गया है और यह पक्का हो गया है कि ग्रीनलैंड के इलाके और वहां के लोगों पर असर डालने वाले फैसलों में ग्रीनलैंड सीधे तौर पर शामिल होगा। उन्होंने कहा, 'ग्रीनलैंड के लिए, यह सिर्फ हमारे बारे में समझौता नहीं है, बल्कि यह हमारे साथ किया गया समझौता है। इसमें ग्रीनलैंड के लोगों, हमारे अधिकारों, हमारी आजीविका और हमारे देश के विकास का ध्यान रखा गया है।' नीलसन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड ने सुरक्षा के लिहाज से अहम भूमिका निभाई थी और वह अमेरिका की घरेलू सुरक्षा में भी मदद करता रहा है। उन्होंने आर्कटिक में सुरक्षा को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच नाटो और पश्चिमी गठबंधन के प्रति ग्रीनलैंड की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। नीलसन ने कहा, 'इस समझौते से आज और भविष्य में इस बात को लेकर कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि ग्रीनलैंड की वफादारी किसके साथ है। हम अमेरिका के पक्के दोस्त रहे हैं और आगे भी रहेंगे, साथ ही पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा भी बने रहेंगे। ' नीलसन ने इस समझौते को 'तीनों पक्षों के लिए फायदेमंद' बताया, जो साझा जिम्मेदारी, आपसी सम्मान और आर्कटिक में शांति बनाए रखने के लक्ष्य पर आधारित है। ट्रंप ने उस पत्रकार के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिसने पूछा था कि क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिका के मालिकाना हक की बात अब खत्म हो गई है। जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड के लोगों के लिए उनका क्या संदेश है, तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे ग्रीनलैंड के लोग बहुत पसंद हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि 'उनके प्रधानमंत्री उनका बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं।' वॉशिंगटन और कोपेनहेगन के बीच 1951 में हुए रक्षा समझौते ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का आधार तैयार किया था। 2004 में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हुए एक समझौते के जरिए इसमें बदलाव किए गए थे।

मेलोनी का बड़ा फैसला, इटली में बुर्का बैन की तैयारी तेज

रोम, एजेंसी। यूरोप के देश इटली में स्कूलों में बुर्का या नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूलों में चेहरा ढकने वाले परिधानों को प्रतिबंधित किया जाएगा। इस कदम के लिए सरकार को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी और संसद की मंजूरी भी जरूरी होगी। इटली का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब कई देशों में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब को लेकर अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लागू हैं। फ्रांस यूरोप का पहला देश था, जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह ढकने पर प्रतिबंध लागू किया था। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड समेत कई यूरोपीय देशों ने भी पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाए।

किन-किन देशों में प्रतिबंधित है, बुर्का : वर्तमान में करीब 24 देशों का उल्लेख किया गया है, जहां बुर्का या नकाब पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध या कड़े प्रतिबंध लागू हैं। इनमें कई लोकतांत्रिक और तानाशाही देश शामिल हैं, साथ ही साथ कुछ मुस्लिम बाहुल्य देश भी हैं जहां बुर्का या नकाब बैन है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, चाड, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, गैबॉन, कोसोवो, किर्गिस्तान, लातविया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के नाम शामिल किए जाते हैं। हालांकि, इन सभी देशों में प्रतिबंध की प्रकृति और दायरा एक जैसा नहीं है। कहीं पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिबंध है तो कहीं स्कूल, सरकारी संस्थान या विशेष सार्वजनिक स्थानों तक इसे सीमित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान होगी वार्ता? विदेश मंत्री रूबियो बोले- ईरान से चर्चा को तैयार अमेरिका इटली कर रहा बुर्का बैन की तैयारी इटली में भी 1975 से सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा कानून ऐसे साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, जिनसे व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो। इस कानून की व्याख्या को लेकर बुर्का और नकाब को शामिल करने पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी स्कूलों में बुर्के को प्रतिबंधित करने की तैयारी तेज कर दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार इटली में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार चेहरा छुपाने पर प्रतिबंध की तैयारी कर रही है। वहीं, हर यूरोपीय देश में ऐसा प्रतिबंध नहीं है। स्वीडन में बुर्का और नकाब पर देशव्यापी प्रतिबंध नहीं है। कुछ स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास हुए, लेकिन उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान ने 2 हजार पूर्व अफगान सैनिक भर्ती किए

क्वेटा, एजेंसी। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल पर दबाव बढ़ रहा है। इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान ने 2,000 पूर्व अफगान सैनिकों और पुलिसकर्मियों भर्ती किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें ज्यादातर वे अफगान सैनिक हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक पूर्व अफगान सैनिक के मुताबिक, भर्ती हुए लोगों को हर महीने 40 हजार पाकिस्तानी रुपए, यानी करीब 13,807 भारतीय रुपए मिलते हैं।

बलूचिस्तान में 2 महीने में 172 हमले, 68 सुरक्षाकर्मी मारे गए : बलूचिस्तान में सुरक्षा ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद विद्रोही थानों, सरकारी दफ्तरों और हाईवे को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा और हिंसा से जुड़े मामलों पर रिसर्च करने वाली संस्था क्कढ्ढष्टस्स् के मुताबिक, दो महीने में बलूचिस्तान में 172 हमले हुए। अकेले जुलाई में विद्रोही हमलों और सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान 62 सुरक्षाकर्मी मारे गए। हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नौश्की शहर में विद्रोहियों से नियंत्रण वापस लेने के लिए पाकिस्तानी सेना को हेलिकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ा। तालिबान की वापसी के बाद नौकरी गई, आर्थिक तंगी ने भर्ती को मजबूर किया अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद कई पूर्व अफगान सैनिकों की नौकरी और तनख्वाह बंद हो गई। बदले के डर से इनमें से कई पाकिस्तान चले आए। 2021 से 2023 के बीच पूर्व सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों की 218 हत्याएं हुईं। ऐसे माहौल में उनके लिए अफगानिस्तान वापस जाना मुश्किल था। पाकिस्तान आने के बाद इन लोगों के पास कोई काम नहीं था। पैसों की दिक्कत बढ़ती गई। ऐसे में जब सुरक्षा बल में नौकरी मिली, तो उन्होंने इसे अपना लिया। पाकिस्तान को इन सैनिकों से क्या फायदा? इन पूर्व अफगान सैनिकों को हथियार चलाने और लड़ाई का पहले से अनुभव है। वे तालिबान के खिलाफ लड़ चुके हैं और सीमावर्ती इलाकों में काम कर चुके हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षा से जुड़े काम समझाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पाकिस्तान के लिए इसका एक फायदा यह भी है कि इन लोगों को पहले से सैन्य ट्रेनिंग मिली हुई है।

न्यूयॉर्क: यूएन मुख्यालय के पास मिला संदिग्ध पैकेट, बम की आशंका, सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट; पुलिस ने क्या बताया?

न्यूयॉर्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। यह पैकेट 43वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के पास मिला था। मामला संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से कुछ ही दूरी का था, जहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख महासभा के उच्चस्तरीय सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने 42वीं स्ट्रीट से 44वीं स्ट्रीट तक और सेकंड एवेन्यू से लेक्सिंगटन एवेन्यू के बीच का इलाका बंद कर दिया। लोगों से इस क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। यह पैकेट 43वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के पास मिला था। मामला संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से कुछ ही दूरी का था, जहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख महासभा के उच्चस्तरीय सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने 42वीं स्ट्रीट से 44वीं स्ट्रीट तक और सेकंड एवेन्यू से लेक्सिंगटन एवेन्यू के बीच का इलाका बंद कर दिया। लोगों से इस क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई।

जांच के बाद पैकेट को लेकर क्या सामने आया : न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने बाद में बताया कि पैकेट की जांच कर ली गई है और उसे संदिग्ध नहीं पाया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता के अनुसार, 22 सितंबर को करीब दोपहर तीन बजे सुरक्षा एजेंसियों और उनके सहयोगी दलों ने 43वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के आसपास के रास्ते एहतियात के तौर पर बंद किए थे। जांच के बाद साफ हुआ कि इस सामान से आम लोगों को कोई खतरा नहीं था। इसके बाद इलाके को फिर से खोला गया। हालांकि पुलिस ने 43वीं स्ट्रीट के थर्ड एवेन्यू से लेक्सिंगटन एवेन्यू तक के हिस्से को कुछ समय के लिए बंद रखा।

इलाके में मौजूद लोगों ने क्या बताया : घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी। पास की एक इमारत में काम करने वाले न्यूयॉर्क निवासी ने बताया कि सड़कें बंद होने के साथ कई मोटरकेड भी इलाके से गुजर रहे थे। उसने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बताया और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि थर्ड एवेन्यू को 42वीं स्ट्रीट के उत्तर में कुछ घंटों के लिए घेर दिया गया था। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। उसने बताया कि उसे लगा कि कोई सूटकेस या सामान मिला था, जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। यह घटना ऐसे समय हुई, जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। उच्चस्तरीय आम बहस 22 से 26 सितंबर और फिर 28 सितंबर को होनी है।

ब्रिटेन के नए पीएम से मिले ट्रंप: दोनों देशों के रिश्तों को बताया बेहतर, चागोस द्वीप समझौते पर भड़के?

न्यूयॉर्क , एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से पहली मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। ट्रंप ने बर्नहम को कारोबार समझने वाला नेता बताया, लेकिन चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने की ब्रिटेन की योजना पर कड़ी आपत्ति जताई। रणनीतिक रूप से अहम डिएगो गार्सिया को लेकर दोनों देशों के बीच क्या मतभेद हैं? बर्नहम इसे कैसे सुलझाएंगे? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं... अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम की न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पहली आमने-सामने मुलाकात हुई। करीब तय समय से ज्यादा चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, यूक्रेन, फॉकलैंड द्वीप, ईरान और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद ट्रंप ने बर्नहम की तारीफ करते हुए उन्हें कारोबार की समझ रखने वाला नेता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के साथ अमेरिका के रिश्ते पिछले प्रधानमंत्री की तुलना में अब बेहतर हैं। बर्नहम ने भी कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छी समझ बनी है।

चागोस द्वीप समझौते पर ट्रंप ने क्यों जताई आपत्ति : दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा मतभेद हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह को लेकर सामने आया। ब्रिटेन ने मॉरीशस को इस द्वीप समूह की संप्रभुता देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही डिएगो गार्सिया द्वीप पर मौजूद रणनीतिक अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की व्यवस्था रखी गई है। हालांकि, इस समझौते को लागू करने के लिए जरूरी ब्रिटिश कानून की प्रक्रिया अमेरिकी विरोध के बाद रुक गई है। ट्रंप ने बैठक के बाद इस समझौते को बेहद खराब करार दिया और कहा कि डिएगो गार्सिया सैन्य और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप की आपत्ति के बावजूद बर्नहम ने समझौते से पीछे हटने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा रास्ता निकालने के लिए काम कर रहा है, जिससे डिएगो गार्सिया का सैन्य इस्तेमाल लंबे समय तक जारी रह सके। ब्रिटेन पहले ही मॉरीशस के साथ संधि कर चुका है, लेकिन इसे लागू करने के लिए संसद की मंजूरी अभी बाकी है। बर्नहम ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नविन रामगुलाम से भी बातचीत की है और दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों की संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बैठक की बात कही गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा: कश्मीर पर भाषण दे रहे थे एर्दोगन, उधर फोन पर रील्स देखते नजर आए सीरियाई राष्ट्रपति

न्यूयॉर्क , एजेंसी। एक तरफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का मंच सजा है, जहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और नेता वैश्विक चुनौतियों, युद्ध, शांति और कूटनीति जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रख रहे है। इस बीच महासभा में हर नजर नेताओं के भाषण और अहम बैठकों पर थी। लेकिन इसी दौरान सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा का एक अलग ही अंदाज कैमरे में कैद हुआ। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गंभीर चर्चा चल रही थी, उस वक्त उनका ध्यान अपने फोन पर नजर आया। वह उस समय फोन पर इंस्टाग्राम रील्स देखते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

क्या है पूरा मामला : कुर्दिस्तान 24 की रिपोर्ट के अनुसार, यूएनजीए के एक अनौपचारिक फुटेज में अल-शारा को तब आराम से अपना फोन इस्तेमाल करते, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते और रील्स भेजते हुए देखा गया, जब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन पोडियम से भाषण दे रहे थे। वहीं, बता दें कि यह दूसरी बार है जब अल-शारा यूएनजीए में शामिल हुए हैं। इससे पहले 2025 में, लगभग 60 वर्षों में यूएनजीए में विश्व नेताओं को संबोधित करने वाले सीरिया के पहले प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया था।

एर्दोगन अपने भाषण में क्या कहा : इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान एर्दोगन ने मंगलवार को कहा, 'दक्षिण एशिया में यह महत्वपूर्ण है कि कश्मीर मुद्दे सहित सभी विवादों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के तहत बातचीत के जरिए सुलझाया जाए।' एर्दोगन पिछले कुछ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। भारत ने उनके ऐसे बयानों पर लगातार आपत्ति जताई है।

2019 में की थी क्या टिप्पणी : एर्दोगन ने 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर टिप्पणी की थी। सितंबर 2019 में 74वें यूएन महासभा के सत्र में उन्होंने कहा था कि 80 लाख लोग लगभग नाकाबंदी में हैं और दुर्भाग्य से कश्मीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पिछले 72 वर्षों में इस विवाद पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका। एर्दोगन की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने तुर्किये से दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी से बचने को कहा था। एर्दोगन ने इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधनों में कश्मीर का जिक्र किया। 2021 में उन्होंने कश्मीर को 74 साल से जारी समस्या बताया था और ऐसा समाधान निकालने की बात कही थी जो हमारे कश्मीरियों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। भारत ने तब भी उनके बयान पर आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि एर्दोगन की लगातार टिप्पणियां इतिहास और कूटनीति की समझ को नहीं दर्शाती हैं।

अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ने बच्चों के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी और शिक्षा गठबंधन का दायरा बढ़ाया

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने बच्चों के लिए 57 देशों तक अपने वैश्विक प्रौद्योगिकी और शिक्षा गठबंधन का दायरा बढ़ाया है। उन्होंने छह बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के साथ आयोजित एक सभा के दौरान मेलानिया ट्रंप ने 'फोस्टरिंग द फ्यूचर टुगेदर' के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, पोलैंड, यूक्रेन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, पनामा और कनाडा समेत कई देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'हम सब मिलकर संस्कृतियों, भाषाओं, इतिहास और परंपराओं का एक सुंदर संगम हैं। फिर भी, हम एक शाश्वत सत्य के लिए एकजुट हैं। हमारी दुनिया का भविष्य इस बात से तय होगा कि आज हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। '

'फोस्टरिंग द फ्यूचर टुगेदर' का उद्देश्य बच्चों की प्रौद्योगिकी और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। साथ ही, उन्हें नए उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद करना है।

अमेरिका की प्रथम महिला ने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल प्रौद्योगिकी तक पहुंच ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों को यह भी सीखना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारीपूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने कहा, 'हम मानव इतिहास के एक असाधारण दौर में जी रहे हैं। हम एक तकनीकी क्रांति की दहलीज पर एक साथ खड़े हैं। नए निजी क्षेत्र के साझेदार एडोब, अमेजन, गूगल, इंटेल, स्टारलिंक और जूम हैं। इस कार्यक्रम में एप्पल के टिम कुक और पेपाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनरिक लोरेस भी उपस्थित थे।

उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल कंप्यूटर, स्वचालित वाहन, आभासी वातावरण और बायोमेट्रिक पहचान को उन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जो विज्ञान कथाओं से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरे व्यावसायिक क्षेत्र को बदल रही है और मानवता के लिए अब तक उपलब्ध जानकारी के सबसे बड़े भंडार तक पहुंच के दायरे को बढ़ा रही है। लेकिन सिर्फ पहुंच ही सशक्तिकरण नहीं है। हमें अपने बच्चों को टूल्स देने होंगे और उन्हें यह सिखाना होगा कि उन टूल्स का समझदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए।' प्रथम महिला ने 2026 के शेष बचे समय के लिए 'फोस्टरिंग द फ्यूचर टुगेदर' के चार कार्यक्रमों की भी घोषणा की। वह दिसंबर में फ्लोरिडा के मियामी में गठबंधन के पहले जी20 कार्यक्रम की मेजबानी करेंगी। फिलीपींस की प्रथम महिला लिजा अरानेटा मार्कोस मनीला में आसियान सम्मेलन के दौरान एक कार्यक्रम की मेजबानी करेंगी। पोलैंड की प्रथम महिला मार्टा नवरोका एक यूरोपीय क्षेत्रीय बैठक का आयोजन करेंगी, जबकि सेंट किट्स और नेविस के डियानी प्रिंस-डू कैरेबियन सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। उन्होंने जीवनसाथियों और अन्य नेताओं से बच्चों को ज्ञान के नए क्षेत्रों का पता लगाने, सोच-समझकर जोखिम उठाने और सामाजिक प्रगति में योगदान देने में मदद करने का आह्वान किया। मेलानिया ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान 'फोस्टरिंग द फ्यूचर टुगेदर' पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य शुरू में सरकारों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना था।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक: सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

दीपके का अल्टीमेटमः मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें या राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा

ज्ञानेश कुमार को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए

नई दिल्ली, एजेंसी।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने गुरुवार (24 सितंबर) को दिल्ली में एक प्रेसवार्ता में कहा कि ज्ञानेश कुमार तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा, इस आंदोलन को जंतर मंतर पार्ट 2 कहा गया है। दीपके ने चुनाव आयोग और एसआईआर (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें देश का सबसे बड़ा गद्दार और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।

दीपके ने सवाल उठाया कि जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, केंद्र सरकार यह तय कर रही है कि कौन मतदान करेगा और कौन नहीं, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के पूरी तरह से खिलाफ है। प्रेसवार्ता में मौजूद सीजेपी के अन्य नेताओं, सौरव दास और आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने, उनके पीछे के आदेश देने वालों की पहचान उजागर करने, एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मौजूदा कानून को बदलने की मांग की।

दीपके ने अपने आरोपों के समर्थन में आंकड़े पेश किए। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में 2 करोड़ से अधिक, उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से अधिक, पश्चिम बंगाल में 90 लाख, दिल्ली में 47 लाख, केरल में 24 लाख, तमिलनाडु में 97 लाख, कर्नाटक में 1 करोड़ और तेलंगाना में 73 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए हैं। दीपके के अनुसार, देश भर में कुल 13 करोड़ से अधिक वोट हटाए गए हैं, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच 2 प्रतिशत के वोट अंतर को देखकर करीब 13 से 14 प्रतिशत वोटों का विलोपन है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वोटों को जानबूझकर हटाया गया ताकि सत्तारूढ़ दल की जीत सुनिश्चित हो सके और वे सत्ता से बाहर न हो पाए, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत हासिल न कर पाने (240 सीटें) के बाद किया गया।

दीपके ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में एक साथ आए क्षेत्रीय नेताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने ममता बनर्जी, एम.के.स्टालिन और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं का उल्लेख कर दावा किया कि उनकी सीटों पर बड़ी संख्या में वोटों को हटाया गया, जिससे चुनाव परिणामों पर असर पड़ा। दीपके ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि ज्ञानेश कुमार की असाधारण परफॉरमेंस को देखकर उन्हें अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ऐसी सीटें जीत रही है और ऐसा वोट प्रतिशत हासिल कर रही है, जो पीक मोदी लहर के दौरान भी नहीं मिला था, जबकि देश में सरकार के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देने की अपनी मांग दोहर दी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा- फ्री एलपीजी पर घमासान, 12 की जगह 6 सिलेंडर का ऐलान

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को फ्री एलपीजी सिलेंडर को लेकर ज़ोरदार हंगामा हुआ। फूड, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने योग्य परिवारों को 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की नीति को मंज़ूरी दे दी है। इस घोषणा पर विपक्ष ने तुरंत कड़ी आपत्ति जताकर आरोप लगाया कि उमर सरकार अपने वादे से मुकर गई है। नेता शर्मा ने याद दिलाया कि लगभग दो साल पहले सरकार ने हर घर के लिए 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि वादे की संख्या को घटाकर 6 करना लोगों के साथ मज़ाक और बड़ा धोखा है। सदन में विपक्ष ने झूठी सरकार और यह धोखा है जैसे नारे लगाए। शर्मा ने सरकार पर लोगों के सामने बेनकाब होने और अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि उमर सरकार के एक लाख नौकरियों के पहले के वादे का क्या हुआ। तीखी बहस के बाद भी, विपक्ष ने कार्यवाही के दौरान लगातार नारेबाजी जारी रखी, जिससे सदन में गहमागहमी बनी रही।

गाड़ी टकराने पर अभिषेक बनर्जी ने पुलिसकर्मी को कराया सस्पेंड, कोर्ट ने किया बहाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निलंबित चल रहे एक पुलिसकर्मी को करीब 6 साल सस्पेंड होने के बाद बहाल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की नाराजगी के चलते उन्हें हटाया गया था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अभिषेक बनर्जी विदेश में आंख का इलाज कराने गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मामला 2023 का है। तब पुलिस ड्राइवर अपनी कार निकाल रहे थे। उस दौरान गाड़ी अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के गेट से टकरा गई थी। इसके बाद उन्हें काम से हटा दिया गया था। खबर है कि राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट में जस्टिस तपोब्रता चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ प्रतिम रॉय की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने पुलिस विभाग को चार सप्ताह के अंदर नए आदेश जारी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी ने गलती की थी, लेकिन गलती इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे काम से ही हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे भी कोई आरोप नहीं हैं कि हादसे में कोई घायल हो गया था। बेंच ने कहा कि इस मामले में कम सजा देने की भी गुंजाइश थी। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर का नाम धीरेंद्रनाथ महतो है और उन्होंने साल 2000 में एक ड्राइवर के तौर पर कोलकाता पुलिस में शुरुआत की थी। बाद में 2005 में उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें हल्की और मध्यम स्तर की जिम्मेदारियां दी जाने लगी थीं।

प्रियंका गांधी तीखा वार : लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ देश के साथ गद्दारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच आयोग पर हमलावर है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करना देश के साथ गद्दारी के समान है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मतदाता सूची में कथित हेरफेर और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाया जाना, जो रिपोर्ट के अनुसार 13 करोड़ से अधिक हो सकता है, लोकतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ एक आपराधिक कृत्य है। प्रियंका गांधी का यह बयान एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते दस महीनों में आयोग के कुछ फैसलों पर करीब 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिसमें एसआईआर से संबंधित फैसले भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ करता है, वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि अगर किसी चुनाव आयुक्त की जानकारी में कोई गैरकानूनी काम हुआ है, तब उस कानूनी सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इन कथित अनियमितताओं की जानकारी थी और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्तों ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था, लेकिन इसके बावजूद इन आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। प्रियंका गांधी ने मांग की कि यदि किसी चुनाव आयुक्त ने गैरकानूनी काम किया है, तब उसके खिलाफ भी अन्य मामलों की तरह आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले जो बातें कही थीं, वे अब सही साबित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को दूषित किया गया है और दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति व्यक्त की थी, जबकि आयोग असहमति न होने की बात कह रहा है। कांग्रेस सांसद मसूद ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण चुनाव प्रभावित होने का भी आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बहु-सदस्यीय आयोग में लिखित टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां आंतरिक विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं। आयोग का कहना है कि एसआईआर समेत सभी प्रमुख फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

मुस्लिमों के मुद्दे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे : जमीयत

नई दिल्ली (एजेंसी)। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भारतीय मुसलमानों को कथित तौर पर निशाना बनने पर गहरी चिंता जताकर घोषणा की है कि संगठन इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला कर कहा कि भारत में एक खास तबके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि इन मामलों को वैश्विक मंच पर उठाया जाएं।

मौलाना मदनी ने अपने में जोर दिया कि आज की तारीख में दुनिया एक वैश्विक गांव बन चुकी है और भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण दोस्त बनाए हैं। उन्होंने कहा, हम उन दोस्तों को साथ लेने वाले हैं, ताकि भारत अपने रास्ते से भटके नहीं। मदनी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन दोस्तों को शामिल करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश सही दिशा में बना रहे और पटरी से न उतरे, जिस जगह पर भारत को रहना चाहिए।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मदनी ने मुल्क में लगातार खास तबके को निशाना बनाने का आरोप लगाकर पिछली घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुईं, फिर घरों पर बुलडोजर चलाए और अब मस्जिदों तथा दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने संवैधानिक राहत के अवसरों को भी छीने जाने को अराजकता की ओर ले जाने वाला बताया, जिससे देश में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है।

इस गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की आपात बैठक बुलाई गई, जहां विस्तृत चर्चा हुई। मौलाना मदनी ने कहा कि केंद्र सरकार, प्रशासन की कथित मिलीभगत और देश की न्यायिक प्रणाली की विफलता ने इस हालात को जन्म दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी खुद को असहाय महसूस करती है, तब यह देश के लिए ठीक नहीं होगा। जमीयत ने संवैधानिक तरीकों से इस स्थिति से लड़ने का संकल्प लिया है।

यह महत्वपूर्ण बैठ नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय की महमूदिया लाइब्रेरी में हुई। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी सहित देश के विभिन्न हिस्सों से कार्यसमिति के सदस्यों ने भाग लिया।

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल के परिजनों से राहुल गांधी ने की फोन पर बात

-परिवार का किया समर्थन और न्याय दिलाने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा

नई दिल्ली , एजेंसी।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के परिजनों से बातचीत की। छात्र साहिल ने पिछले हफ्ते आईआईटी पवई परिसर में आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी ने आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के परिजनों से फोन पर बातचीत की है। राहुल ने पीड़ित परिवार को अपना समर्थन दिया और न्याय दिलाने में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मामले को लेकर गुरुवार दोपहर में यूथ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इसमें साहिल वाकोडे मामले को लेकर आगे की रणनीति और आंदोलन की दिशा की घोषणा किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साहिल की मौत के बाद उनके परिवार ने आईआईटी बॉम्बे प्रशासन और कुछ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। बता दें छात्र साहिल ने परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। वह ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग में द्वितीय वर्ष का छात्र था। संस्थान का कहना है कि वाकोडे ने परीक्षा के दौरान चैटजीपीटी से सवालों का जवाब पाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा प्रशिक्षक और विभाग के प्रमुख ने छात्र से इस मामले पर बातचीत की।

अखिलेश भी मान रहे हैं भगवा ही जीतेगा, इसलिए पीडीए रथ भी भगवा रंग में है

बीजेपी नेता दयाशंकर ने रायबरेली से पीडीए रथ यात्रा को लेकर साधा निशाना

लखनऊ, एजेंसी।
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने रायबरेली से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश खुद पीडीए की परिभाषा को लेकर स्पष्ट नहीं हैं। समय-समय पर वह पीडीए की अलग-अलग व्याख्या करते हैं। दयाशंकर ने कहा कि कभी पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया जाता है, तो कभी इसमें पंडित और आधी आबादी को शामिल किया जाता है। उन्होंने इसे अखिलेश यादव का जुमला बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच पीडीए की नहीं, बल्कि परिवारवादी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दयाशंकर ने अखिलेश की रथयात्रा के भगवा रंग में होने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भगवा रंग को लेकर प्रदेश की जनता में बढ़ते रुझान को देखते हुए अखिलेश ने अपने पीडीए रथ को भी भगवा रंग में बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की वापसी होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश भी मानकर चल रहे हैं कि भगवा ही जीतेगा, इसलिए उनका रथ भी भगवा रंग में है।

बता दें अखिलेश यादव आज रायबरेली में पहली बार पीडीए रथ चलाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी को गति देंगे। अपने सहयोगी दल कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से इसकी शुरुआत कर सपा अलग संदेश देने का प्रयास भी करेगी। रायबरेली में 17 सितंबर को फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद जिले में युवा राजनीति गरमाई है। ऐसे समय में सपा रथयात्रा कर अपना अलग संदेश देने का प्रयास करेगी। अखिलेश की इस यात्रा को रायबरेली में संगठन को सक्रिय करने की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

सपा प्रमुख व अन्य नेता रथ से रायबरेली में सपा विधायक राहुल लोधी के आवास पहुंचेंगे। यहां वह करीब साढ़े तीन घंटे तक रहेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश पहली बार रथ की झलक दिखाने के साथ ही राजनीतिक संदेश भी देंगे। रथयात्रा की शुरुआत के लिए रायबरेली को चुनने के पीछे एक वजह इस जिले की तीन सीटों पर सपा विधायकों का जातीय समीकरण भी माना जा रहा है।

लद्दाख के लिए वांगचुक की पदयात्रा, सीजेपी के बड़े नेता नदारद

उपराज्यपाल ने वापस लिए 20 केस

नई दिल्ली, एजेंसी।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में 26 दिनों तक अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बदले में वह व्यापक साथ नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने आवाज लगाई थी। सोनम वांगचुक की लद्दाख पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए सीजेपी का एक भी बड़ा नेता लद्दाख नहीं गया। अभिजीत दीपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समर्थन की बात तो कही थी, लेकिन खुद वहां जाने से परहेज कर गए।

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर 2025 को केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। इसकी पहली बरसी के उपलक्ष्य में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को लेह में एक प्रतीकात्मक पदयात्रा का नेतृत्व किया। 24 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले सोनम वांगचुक ने 19 से 24 सितंबर तक पदयात्रा की घोषणा करते हुए कॉकरोचों (सीजेपी सदस्यों) से भी इसमें शामिल होने की अपील की थी। दिल्ली से बनाए एक वीडियो में वांगचुक ने जंतर-मंतर पर अपने अनशन की याद दिलाते हुए कहा था कि वह अब कॉकरोचों से मदद चाहते हैं।

वांगचुक की अपील पर अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने लद्दाख के समर्थन की बात सोशल मीडिया पर लिखी थी। हालांकि, इनमें से किसी नेता ने ना तो लद्दाख जाने की घोषणा की थी और ना ही इनकार किया था। बाद में वांगचुक ने खराब मौसम को देखते हुए चार दिन की यात्रा स्थगित कर दी और सिर्फ 23 सितंबर को एक दिन की पदयात्रा की घोषणा की। बुधवार को जब कुछ दर्जन यात्रियों के साथ वांगचुक लेह की ओर रवाना हुए तो उनके साथ लद्दाख के अलावा कुछ दूसरे प्रदेशों से आए लोग भी थे। हालांकि, सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका वहां नजर नहीं आए। पदयात्रा के दौरान एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वांगचुक ने कहा कि उन्होंने एक बार अधिक से अधिक लोगों के आने की अपील की थी, लेकिन बाद में इस पर अधिक जोर नहीं दिया, जो आए उनका स्वागत किया गया है।

महुआ बोलीं- आयुक्तों को डरने की जरुरत नहीं है हम हैं न...

नई दिल्ली, एजेंसी।
चुनाव आयोग में कथित मतभेद को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने का सिलसिला जारी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि दोनों आयुक्तों को अपने निर्णयों में स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि सरकार दोनों चुनाव आयुक्तों, उनके परिवार और सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी अपील किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर है। महुआ ने अपने राजनीतिक जीवन में सदस्यता समाप्त होने और जांच एजेंसियों की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि वह दबाव के आगे नहीं झुकी थीं। उन्होंने चुनाव आयुक्तों से भी इसी तरह अपने फैसलों पर कायम रहने की अपील की।

महुआ ने कहा कि मौजूदा समय में चुनाव आयोग से जुड़े फैसलों को इतिहास के संदर्भ में भी देखा जाएगा। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए आयुक्तों से पीछे नहीं हटने का आग्रह किया। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी चुनाव आयोग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को लेकर कई सवाल उठाए हैं। आयोग ने आंतरिक टिप्पणियों को निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बताते हुए कहा है कि पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। थरूर का कहना है कि सर्वसम्मति से अंतिम निर्णय होने की जानकारी से प्रक्रिया के दौरान उठाई गई आपत्तियों से जुड़े सवालों का पूरी तरह जवाब नहीं मिलता। उन्होंने पूछा कि क्या कथित 14 आपत्तियां वास्तव में दर्ज की गई थीं और यदि दर्ज हुई थीं तो प्रत्येक पर क्या निर्णय लिया गया। थरूर ने फॉर्म-6 में बदलाव के कानूनी आधार तथा मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों तक पहुंच को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने गोवा में कथित 97 मतदाताओं से जुड़े मामले और बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ दायर अपीलों को लेकर भी सवाल उठाए। थरूर ने चुनाव आयोग से इन सभी मुद्दों पर बिंदुवार और दस्तावेजी जवाब देने की मांग की है।

करीब पांच करोड़ लोग आ सकते हैं भुखमरी के संकट की चपेट में

नई दिल्ली,, एजेंसी।
एशिया महाद्विप में करीब पांच करोड़ लोग भुखमरी के संकट की चपेट में आ सकते हैं। यह चेतावनी दी है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। अल नीनो के मजबूत होने की चेतावनियों के बीच खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अल नीनो के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होते पानी और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मिलकर स्थिति को और गंभीर बना सकता है। भारत में भी मानसून के दौरान इसके संकेत दिखाई देने की बात कही जा रही है। जून से सितंबर के बीच कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रही है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सूखे जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है। इसका असर खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। चावल, दाल, कपास और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन प्रभावित होने पर आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

इसका सबसे अधिक असर कम आय वाले परिवारों पर पड़ने की आशंका है। भारत सरकार ने संभावित स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील जिलों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर जोर दिया है। किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली और कम अवधि की फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दालों और बाजरे जैसी फसलों को भी विकल्प के तौर पर बढ़ावा देने की बात कही गई है। श्रीलंका में भी सूखे का असर गंभीर बताया जा रहा है। एक लाख साठ हजार से अधिक लोगों के पेयजल संकट से प्रभावित होने की बात सामने आई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर घट गया है। कुछ क्षेत्रों में पशुओं और वन्यजीवों के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है।

देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने की योजना पर भी काम कर रही है, हालांकि उसकी मौजूदा क्षमता सीमित है। दक्षिण-पूर्व एशिया में चावल उत्पादन को लेकर भी चिंता है। क्षेत्रीय उत्पादन में आठ से दस प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान बताया गया है। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। ऐसे में उत्पादन घटने से कीमतों में वृद्धि का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ सकता है। पूर्वी एशिया में भी गर्मी, भारी बारिश और तूफानों का खतरा बना हुआ है। दक्षिण कोरिया में सूखे के बाद अचानक भारी बारिश देखने को मिली। जापान में कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने की घटनाएं सामने आई हैं। चीन, हांगकांग और ताइवान में भी अत्यधिक गर्मी और जलवायु जोखिम से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।